नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 111
दि. 23.01.2026,
शुक्रवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

महापौर की कुर्सी पर मातृशक्ति की दस्तक, महाराष्ट्र की सियासत में नया अध्याय

मुंबई। महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में एक बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव सामने आया है। राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के महापौर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी के ऐलान के साथ ही यह साफ हो गया है कि आने वाले कार्यकाल में महानगरों की सत्ता में महिलाओं की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने जा रही है। बीएमसी से लेकर नागपुर तक कुल 15 नगर निगमों में महिला महापौर चुनी जाएंगी। यह केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि शहरी शासन में महिला नेतृत्व के विस्तार की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक तस्वीर भी पेश करता है। हालांकि इस फैसले के साथ ही राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप, असंतोष और रणनीतिक गणनाओं का दौर भी तेज हो गया है, खासकर मुंबई महानगरपालिका को लेकर।

राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को शहरी विकास मंत्री माधुरी मिसाल की मौजूदगी में 29 नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में महापौर पदों का वर्गीकरण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ओपन कैटेगरी के तहत किया गया। इस प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट हुआ कि कुल 29 में से 15 महापौर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, धुले, मीरा-भयंदर, नवी मुंबई, नांदेड़-वाघला, मालेगांव जैसे बड़े और राजनीतिक रूप से अहम नगर निगम शामिल हैं। ओपन कैटेगरी महिला के लिए 9 नगर निगमों में महापौर पद आरक्षित किया गया है, जबकि ओबीसी महिला, अनुसूचित जाति महिला और अनुसूचित जनजाति से भी महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। सबसे ज्यादा चर्चा बृहन्मुंबई महानगरपालिका यानी बीएमसी को लेकर हो रही है। देश के सबसे बड़े नगर निगम में इस बार महापौर पद ओपन कैटेगरी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। बीएमसी का राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक महत्व किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में यहां महिला महापौर का चुना जाना न केवल मुंबई, बल्कि पूरे राज्य की राजनीति के लिए अहम संकेत देता है।

भाजपा ने इसे गर्व का विषय बताते हुए कहा है कि मुंबई को दिशा देने, भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत

करने की जिम्मेदारी अब एक महिला के हाथों में होगी। भाजपा मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने दावा किया है कि अगले दो-तीन दिनों में पार्टी के भीतर बैठकें कर सभागृह नेता का चयन किया जाएगा और वही महापौर बनेगा।

हालांकि, इस आरक्षण लॉटरी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट यानी शिवसेना (यूबीटी) ने तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। ठाकरे गुट का आरोप है कि बीएमसी के लिए नियम बदले गए और आरक्षण प्रक्रिया को सत्ताधारी दलों के हित में मोड़ा गया। उनका कहना है कि बीएमसी में इस बार महापौर पद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होना चाहिए था। शिवसेना (यूबीटी) का तर्क है कि अगर एसटी महिला के लिए आरक्षण होता, तो उनके पास 'किंगमेकर' बनने का सुनहरा मौका था, क्योंकि बीएमसी में एसटी कैटेगरी के जो दो पार्षद हैं, वे दोनों ही ठाकरे गुट से आते हैं। पार्टी का दावा है कि नियमों में तकनीकी बदलाव कर यह संभावना खत्म कर दी गई। इस पूरे विवाद का केंद्र वह नियम है, जिसके तहत किसी भी आरक्षण श्रेणी को लागू करने के लिए कम से कम तीन निर्वाचित सदस्य होना जरूरी है। बीएमसी में अनुसूचित जनजाति के केवल दो ही पार्षद होने के कारण एसटी आरक्षण लागू नहीं किया गया। इसी आधार पर ओपन कैटेगरी महिला के लिए महापौर पद तय किया गया। ठाकरे गुट ने इसे राजनीतिक चाल बताते हुए लॉटरी प्रक्रिया का बहिष्कार किया। बीएमसी की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर ने आरोप लगाया कि यह लॉटरी शासकों की संख्या और राजनीतिक गणित को देखकर की गई है और इससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय हुआ है।

विपक्षी दलों ने भी इस प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने आरोप लगाया कि लॉटरी सिस्टम पहले से फिक्स था और सत्ताधारी गठबंधन को फायदा पहुंचाने के लिए आरक्षण तय किया गया। विपक्ष का कहना है कि बीएमसी जैसे बड़े नगर निगम में आरक्षण का फैसला पारदर्शिता और सामाजिक संतुलन के आधार पर होना चाहिए था, न कि राजनीतिक लाभ-हानि को ध्यान में रखकर। शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव परिणामों के बाद उद्धव ठाकरे ने जिस भरोसे के साथ कहा था कि मुंबई में उनकी पार्टी का मेयर होगा, वह उम्मीद अब इस लॉटरी के साथ टूट गई है। दूसरी ओर, सत्ताधारी महायुति के भीतर भी तस्वीर पूरी तरह सरल नहीं है। भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के बीच कई नगर निगमों को लेकर पहले से ही खींचतान चल रही थी। मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और उल्हासनगर जैसी बड़ी महानगरपालिकाओं में महायुति की सत्ता लगभग तय मानी जा रही है, लेकिन इन निगमों में महापौर पद किस दल के खाते में जाएगा, इस पर अंतिम फैसला अभी बाकी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस समय दावोस दौरे पर हैं और 25 जनवरी को मुंबई लौटेंगे। उनके लौटने के बाद भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) के शीर्ष नेताओं के बीच बैठक होने की संभावना है, जिसमें महापौर पदों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगेगी। मुंबई में भाजपा के भीतर भी महापौर पद को लेकर अंदरूनी राजनीति तेज हो गई है। पार्टी के गलियारों में सबसे मजबूत दावेदार के रूप में अलका केरकर का नाम लिया जा रहा है, जो तीन बार की पार्षद रह चुकी हैं और उपमहापौर का अनुभव भी रखती हैं। इसके अलावा रितू तावडे और राजश्री शिरवाडकर जैसे नाम भी चर्चा में हैं। भाजपा नेतृत्व ऐसे चेहरे की तलाश में है जो प्रशासनिक अनुभव के साथ-साथ मुंबई की जटिल सामाजिक संरचना, खासकर मराठी और गैर-मराठी समीकरण को संतुलित कर सके। यह फैसला आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति से भी जुड़ा माना जा रहा है।

राज्य के अन्य हिस्सों में भी महापौर पदों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अकोला में ओबीसी महिला के लिए महापौर पद आरक्षित होने के बाद भाजपा को सत्ता से दूर रखने के लिए विपक्षी दलों ने एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के निवास पर कांग्रेस, एआईएमआईएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों की बैठक हुई, जिसमें महापौर पद को लेकर गहन चर्चा की गई। यह बैठक इस बात का संकेत है कि कई नगर निगमों में मुकाबला केवल सत्ताधारी और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर जटिल गठबंधनों और रणनीतियों का भी होगा।

इन तमाम राजनीतिक उठापटक के बीच एक बात साफ है कि इस बार महाराष्ट्र की शहरी राजनीति में महिला नेतृत्व पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। 15 महिला महापौरों का चुना जाना केवल आरक्षण का परिणाम नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक और राजनीतिक मिजाज का भी संकेत है। शहरी निकायों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से नीतियों और प्रशासन में संवेदनशीलता, समावेशिता और जमीनी मुद्दों पर फोकस बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि, यह भी सच है कि इन महिला महापौरों की राह आसान नहीं होगी। उन्हें न केवल प्रशासनिक चुनौतियों से जूझना होगा, बल्कि पुरुष-प्रधान राजनीतिक ढांचे में अपनी मजबूत पहचान भी बनानी होगी।

राहुल गांधी ने मजदूरों के समर्थन में मनरेगा बचाओ मोर्चा को संबोधित किया

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जवाहर भवन में आयोजित 'मनरेगा बचाओ मोर्चा' कार्यक्रम में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित 'विकसित भारत जी राम जी अधिनियम' को लेकर तीखा हमला बोला। इस अधिनियम के तहत कथित रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) को समाप्त कर उसकी जगह नया कानून लाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि अगर देश के गरीब और मजदूर इस कानून के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे, तो सरकार को इसे वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में इतिहास और सामाजिक आंदोलनों का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह किसानों ने काले कृषि कानूनों के खिलाफ एकजुट होकर सरकार को पीछे हटने पर मजबूर किया था, उसी तरह अब मजदूरों के पास भी यही शक्ति है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार अब वही हमला मजदूरों पर कर रही है, जो पहले किसानों के खिलाफ किया गया था। उनका कहना था कि भाजपा ऐसा भारत चाहती है, जहाँ सभी फैसले केवल एक व्यक्ति के हाथ में हों, और लोकतांत्रिक संस्थाओं और गरीब तबके के अधिकारों की उपेक्षा की जा रही है।

कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मनरेगा को समाप्त करना सीधे गरीबों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश है। खरगे ने इसे महात्मा गांधी के नाम और उनके आदर्शों के खिलाफ एक हमला बताया और कहा कि देश इसे कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस बजट सत्र में इस मुद्दे को जोरशोर से उठाएगी और मनरेगा को बचाने के लिए पूरे देश में आंदोलन करेगी। उनका कहना था कि कांग्रेस तब तक संघर्ष जारी रखेगी जब तक केंद्र सरकार नया कानून वापस नहीं लेती और मनरेगा को बहाल नहीं करती।

इस अवसर पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रतीकात्मक रूप से मजदूरों के समर्थन का संदेश देने के लिए विशेष वेशभूषा अपनाई। दोनों नेताओं ने सिर पर गमछा बांधा और हाथ में कुदाल उठाकर यह संदेश दिया कि मजदूरों के अधिकारों के लिए कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। इस दृश्य ने कार्यक्रम को प्रतीकात्मक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। राहुल गांधी ने कहा कि मजदूरों की एकजुटता ही देश में न्याय और समानता की लड़ाई की सबसे बड़ी ताकत है।

उन्होंने आगे कहा कि मनरेगा केवल रोजगार देने की योजना नहीं है, बल्कि यह गरीबों और ग्रामीण भारत के सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसे समाप्त करना सीधे ग्रामीण जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि इस योजना के बिना ग्रामीण युवा और महिला श्रमिकों की आजीविका संकट में पड़ सकती है।

राहुल गांधी ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस इस मुद्दे को केवल राजनीतिक बहस के रूप में नहीं देख रही है, बल्कि इसे देश के गरीब तबके के अधिकारों और उनके जीवन के लिए एक राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में देखा जा रहा है। उन्होंने मजदूरों से अपील की कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों और यह सुनिश्चित करें कि उनके हक पर कोई आघात न हो।

कार्यक्रम में उपस्थित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी मजदूरों और गरीब वर्ग के समर्थन का संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा की सुरक्षा और उसका पुनर्स्थापन केवल एक योजना की बहाली नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए जरूरी है।

इस तरह कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया कि वह मनरेगा को बचाने के लिए हर स्तर पर संघर्ष करने को तैयार है, चाहे वह संसद के भीतर हो, न्यायिक मंचों पर हो या जनता के बीच आंदोलनों के माध्यम से। कार्यक्रम का संदेश स्पष्ट था – गरीब और मजदूर यदि एकजुट होंगे, तो कोई भी सरकार उनके अधिकारों को नजरअंदाज नहीं कर सकती।

जुबीन गर्ग मौत मामला: दो आरोपियों ने जमानत याचिका वापस ली, अगली सुनवाई 30 जनवरी को

गुवाहाटी। गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में नया मोड़ आया है। जुबीन गर्ग की मौत के मामले में आरोपितों की जमानत याचिकाओं पर गुरुवार को कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान दो आरोपियों—श्यामकानु महंत और जुबीन के चचेरे भाई संदीपन—ने अपनी जमानत याचिकाएं वापस लेने का फैसला किया।

श्यामकानु महंत, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के निदेशक हैं, पर जुबीन गर्ग की हत्या का गंभीर आरोप है। वहीं, संदीपन असम पुलिस के निलंबित अधिकारी हैं और उन पर गैर-इरादतन हत्या का आरोप है। उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि वे अब जमानत याचिका वापस लेना चाहते हैं, और अदालत ने इसे स्वीकार कर लिया। इसका मतलब है कि दोनों आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए अपनी मांग छोड़ दी है और उनके खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया सामान्य रूप से जारी रहेगी।

सुनवाई के दौरान अदालत ने गायक अमृतप्रवा महंता और जुबीन गर्ग के दो निजी सुरक्षा अधिकारियों परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा की जमानत याचिकाओं पर भी विचार किया। इन तीनों आरोपियों की याचिकाओं पर अदालत ने अभी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है और अगली सुनवाई 30 जनवरी को निर्धारित की गई है। इस दिन अदालत संभवतः जमानत पर अंतिम आदेश सुना सकती है।

इस मामले में कुल सात आरोपियों के खिलाफ जमानत याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें से पांच की सुनवाई वर्तमान में चल रही थी। गुरुवार के फैसले के बाद श्यामकानु और संदीपन की याचिकाएं हट जाने से अब अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर ध्यान केंद्रित होगा।

विशेष रूप से, जुबीन गर्ग के परिवार और सुरक्षा कर्मचारियों से जुड़े मामले में यह सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल व्यक्तिगत आरोपियों की सुरक्षा और कानूनी स्थिति तय करेगी, बल्कि पूरे मामले की सामान्य न्यायिक प्रक्रिया की गति पर भी असर डालेगी।

इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि अदालत में कानूनी रणनीति और वकीलों के फैसले किसी भी समय मामले की दिशा बदल सकते हैं। श्यामकानु और संदीपन ने अपनी याचिकाएं वापस लेकर अदालत पर भरोसा जताया कि वे मामले की न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे की सुनवाई में पेश होंगे और अपने बचाव के लिए अन्य कानूनी उपाय अपनाएंगे। 30 जनवरी की अगली सुनवाई में कोर्ट के निर्णय से यह स्पष्ट हो जाएगा कि अन्य आरोपियों को जमानत मिलेगी या नहीं, और मामले की जांच तथा मुकदमे की गति किस दिशा में बढ़ेगी।

कर्नाटक विधानसभा में अभूतपूर्व सियासी टकराव, बिना पूरा अभिभाषण पढ़े सदन से निकले राज्यपाल

बेंगलुरु। कर्नाटक विधानसभा के इतिहास में गुरुवार का दिन एक असामान्य और तीखे राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में दर्ज हो गया, जब राज्यपाल थावरचंद गहलोत संयुक्त सत्र में पारंपरिक अभिभाषण पूरा पढ़े बिना ही सदन से बाहर निकल गए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम ने न केवल सदन की कार्यवाही को बाधित किया, बल्कि राज्यपाल और सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के बीच पहले से चले आ रहे तनाव को खुलकर सामने ला दिया। राज्यपाल के इस कदम के बाद विधानसभा परिसर में हंगामे का माहौल बन गया और कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया, जिससे पूरे घटनाक्रम ने संवैधानिक मर्यादाओं, परंपराओं और राजनीतिक शिष्टाचार पर नई बहस छेड़ दी।

विधानसभा सत्र की शुरुआत आमतौर पर राज्यपाल के अभिभाषण से होती है, जिसे सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और जिसमें सरकार की नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का उल्लेख रहता है। यह अभिभाषण न केवल संवैधानिक औपचारिकता है, बल्कि सरकार और विधायिका के बीच एक औपचारिक संवाद का माध्यम भी माना जाता है। गुरुवार को भी कर्नाटक विधानसभा के संयुक्त सत्र में इसी परंपरा के तहत राज्यपाल थावरचंद गहलोत का अभिभाषण प्रस्तावित था। तय कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल सदन में पहुंचे, सभी सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर मौजूद थे और वातावरण औपचारिक लेकिन अपेक्षाकृत शांत था।

हालांकि यह शांति ज्यादा देर टिक नहीं सकी। राज्यपाल ने अपने संबोधन की शुरुआत तो की, लेकिन उन्होंने सरकार द्वारा तैयार किए गए पूरे भाषण को पढ़ने के बजाय केवल कुछ पंक्तियां पढ़ीं और अचानक अपना संबोधन समाप्त कर दिया। इसके तुरंत बाद वे सदन से बाहर निकल गए। यह दृश्य इतना अप्रत्याशित था कि कुछ पल के लिए सदन में मौजूद विधायक और अधिकारी भी समझ नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही क्षणों में यह असमंजस हंगामे में बदल गया और कांग्रेस विधायकों ने इसे लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन बताते हुए विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया।

कांग्रेस विधायकों का कहना था कि राज्यपाल का यह व्यवहार न केवल असंवैधानिक है, बल्कि विधानसभा और निर्वाचित सरकार के प्रति असम्मानजनक भी है। उनका आरोप था कि राज्यपाल ने जानबूझकर सरकार के अभिभाषण को पढ़ने से इनकार किया, ताकि राजनीतिक संदेश दिया जा सके। विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। कई कांग्रेस नेताओं ने इसे केंद्र और राज्य के बीच चल रहे राजनीतिक टकराव का विस्तार बताते हुए कहा कि राज्यपाल का पद राजनीतिक दबाव या पक्षपात से ऊपर होना चाहिए।

दूसरी ओर, राज्यपाल के इस कदम को लेकर विपक्षी दलों और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों की राय अलग दिखाई दी। उनका तर्क था कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख हैं और यदि उन्हें किसी भाषण या उसके किसी हिस्से पर आपत्ति है, तो वे उसे पढ़ने से इनकार कर सकते हैं। हालांकि इस तरह का इनकार सार्वजनिक मंच पर और संयुक्त सत्र के दौरान करना कितना उचित है, इस पर भी सवाल उठे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यदि राज्यपाल को सरकार के अभिभाषण की सामग्री पर आपत्ति थी, तो इसके लिए संवाद और परामर्श के अन्य संवैधानिक रास्ते उपलब्ध थे।

इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में राज्यपाल और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के बीच पहले से चले आ रहे मतभेदों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते कुछ महीनों में कई विधेयकों, नीतिगत फैसलों और प्रशासनिक नियुक्तियों को लेकर राजभवन और सरकार के बीच खींचतान देखने को मिली है।

भोजशाला में आस्था और सह-अस्तित्व का संतुलन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टला टकराव

धार। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और संवेदनशील स्थल भोजशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे धार्मिक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के ताजा आदेश ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत की न्यायिक व्यवस्था आस्था, परंपरा और सामाजिक संतुलन के बीच रास्ता निकालने की कोशिश करती है। वसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में हिंदू पक्ष द्वारा मां सरस्वती की पूजा और मुस्लिम पक्ष द्वारा जुमे की नमाज को लेकर उत्पन्न तनाव के बीच शीर्ष अदालत ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिससे दोनों समुदायों को अपनी-अपनी धार्मिक परंपराएं निभाने का अवसर मिल सके और किसी भी तरह की टकराव की स्थिति पैदा न हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि शुक्रवार 23 जनवरी को वसंत पंचमी के दिन भोजशाला परिसर में हिंदू श्रद्धालु पूजा कर सकेंगे, वहीं मुस्लिम समुदाय को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच जुमे की नमाज अदा करने की अनुमति दी जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि नमाज के लिए मंदिर क्षेत्र के भीतर ही एक विशेष स्थान निर्धारित किया जाएगा, ताकि दोनों धार्मिक गतिविधियां अपने-अपने दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सकें। इसके साथ ही पूजा और नमाज दोनों के लिए विशेष पास जारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे भीड़ नियंत्रण और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सुविधा हो। यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब भोजशाला को लेकर भावनाएं एक बार फिर तेज हो गई थीं। हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिका दायर कर मांग की थी कि वसंत पंचमी के दिन, जो मां सरस्वती की पूजा का प्रमुख पर्व माना जाता है, मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने से रोका जाए और केवल हिंदू पक्ष को ही पूजा की अनुमति दी जाए। हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि भोजशाला को ऐतिहासिक रूप से मां सरस्वती का मंदिर माना जाता है और वसंत पंचमी पर यहां पूजा की परंपरा रही है, ऐसे में उस दिन नमाज की अनुमति देने से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं। दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि भोजशाला लंबे समय से विवादित स्थल रहा है, जहां पूर्व में अदालत और प्रशासन के निर्देशों के तहत मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने की अनुमति मिलती रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी एक समुदाय को पूरी तरह रोकना संविधान की भावना और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ होगा। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और कानून के दायरे में रहते हुए दोनों समुदायों की धार्मिक गतिविधियां संभव हैं।

इन दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संतुलित रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष को पूरी तरह वंचित करना उचित नहीं होगा। अदालत ने कहा कि देश की विविधता और बहुधार्मिक परंपरा का सम्मान करते हुए ऐसा समाधान निकाला जाना चाहिए, जिससे दोनों समुदाय अपनी आस्था का पालन कर सकें और सार्वजनिक शांति बनी रहे। इसी सोच के तहत कोर्ट ने पूजा और नमाज दोनों की अनुमति दी, साथ ही समय और स्थान को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी किए।

भोजशाला का इतिहास अपने आप में जटिल और संवेदनशील रहा है। हिंदू पक्ष इसे परमार शासक राजा भोज द्वारा स्थापित सरस्वती मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहां कमाल मौला मस्जिद स्थित है, जहां सदियों से नमाज अदा की जाती रही है। इस स्थल को लेकर समय-समय पर विवाद, आंदोलन और कानूनी लड़ाइयां होती रही हैं। वसंत पंचमी का अवसर हर साल इस विवाद को और अधिक संवेदनशील बना देता है, क्योंकि यह दिन हिंदू समाज के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है।

संपादकीय

आपसी जुड़ाव व लेखन कला निखार की पहल

निस्संदेह डिजिटल दौर के नशे में डूबी पीढ़ी वास्तविक रिश्तों से दूर होती जा रही है। वहीं दूसरी ओर छात्रों की लिखने की आदत भी छूटती जा रही है। लेखन हमारी मौलिक व सार्थक अभिव्यक्ति है और सेहत से भी जुड़ा है। पुरानी कहावत है—जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता। कमोबेश मौजूदा दौर में हकीकत यही है कि जिनके सोशल मीडिया में हजारों-लाखों मित्र व फॉलोवर होते हैं वे निजी जीवन में नितांत एकाकी होते हैं। यह घातक प्रवृत्ति बच्चों में भी तेजी से घर कर रही है। लेखन में हमारी उंगलियों के पोर इस्तेमाल होते हैं, जिनके सिरे हमारे विभिन्न अंगों के स्वास्थ्य से गहरे तक जुड़े रहते हैं। कलम या पेन से लेखन हमारे बौद्धिक विकास में भी सहायक होता है। लेकिन आज मोबाइल व कंप्यूटर, लेपटॉप व टैबलेट के दौर में बच्चे लेखन से दूर होकर खुद को बेहतर ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इस संकट को महसूस करते हुए सीबीएसई ने छात्रों को मित्रों से जुड़ाव व उनकी लेखन कला को निखारने के लिए अभिनव पहल की है। बोर्ड ने डाक विभाग के साथ मिलकर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 'इंटरनेशनल लेटर राइटिंग कंपीटिशन-2026' आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम आने वाले छात्र को पचास हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही विजेता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी दिया जाएगा। छात्रों को जो पत्र लिखने का विषय दिया गया है वह मौजूदा हालात में बेहद रोचक व उपयोगी है। छात्र को अपने दोस्त को पत्र लिखना है कि मौजूदा डिजिटल दौर में लोगों का आपसी जुड़ाव व बातचीत क्यों जरूरी है। दरअसल, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्रों की सोच को विस्तार देना और उनकी लेखन कला को निखारना है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता को जीतने वाले प्रतिभागी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा।

उल्लेखनीय है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतने पर छात्र को स्विट्ज़रलैंड के बर्न स्थित यूपीए हेड क्वार्टर का दौरा करने का अवसर मिल सकता है। इस प्रतियोगिता के प्रतिभागी नौ से पंद्रह साल के ही होने चाहिए। वे अपनी एंट्री अंग्रेजी व हिंदी में भी दे सकते हैं। प्रतिभागी अपने स्कूल के माध्यम से ही इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। निश्चित रूप से बच्चों में लिखने की घटती प्रवृत्ति के दौर में यह एक रचनात्मक प्रयास है। दरअसल, लगातार सोशल मीडिया स्क्रॉल करते बच्चे न केवल रचनात्मक लेखन से वंचित हो रहे हैं, बल्कि अपने दोस्तों से भी कटते जा रहे हैं, जिसका असर उनकी याददाश्त व सृजन क्षमता पर भी पड़ रहा है। एक समय था बच्चे डायरी लेखन व स्कूलों में कविता व लेख लिखने को खासे उत्सुक होते थे। दोस्तों के साथ खेल के मैदान और घर पर खेलना उन्हें शारीरिक व मानसिक स्तर पर स्वस्थ रखता था। लेकिन आज बच्चे ऑनलाइन खेलों में इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें अपने असली दोस्तों का ख्याल ही नहीं रहता। वे जीवन की वास्तविक चुनौतियों से दूर होते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज शारीरिक सक्रियता के अभाव के कारण बच्चे छोटी उम्र में ही वयस्कों जैसे रोगों के शिकार होते जा रहे हैं। ये रोग शारीरिक भी हैं और मानसिक भी हैं। छात्र अपना बचपन स्वाभाविक रूप से नहीं जी पा रहे हैं। सही मायनों में वे समय से पहले वयस्क होते जा रहे हैं। एक समय बच्चों की लेखन क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। परीक्षा में बाकायदा सुंदर लेखन के अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं। लेकिन आज बच्चे इंटरनेट पर उपलब्ध शॉर्टकट के जरिये हर परीक्षा पास करना चाहते हैं। कट-पेस्ट संस्कृति ने उनकी मौलिक सोच व सृजनात्मकता को ग्रहण लगा दिया। अक्सर छात्र प्रतियोगात्मक परीक्षाओं व लेखन प्रतिस्पर्धाओं में ऑनलाइन माध्यमों व इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को हेर-फेर के साथ प्रस्तुत करते देखे जा रहे हैं, जो उन्हें व्यावहारिक जीवन की प्रतिस्पर्धा में कमजोर बनाता है। ऐसे में सीबीएसई व पोस्टल विभाग की पहल अनुकरणीय व प्रशंसनीय है।

केरल, कर्नाटक और तेलंगाना- पहले दिन ही ताबड़तोड़ ऐलान कर नितिन नवीन ने अपने इरादे बता दिए

> बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी या यूं कहें कि सबसे पहली चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव है। क्योंकि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नवीन के पास होने या फेल होने की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी।

देश की सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को अब तक का अपना सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन (45 वर्ष) के रूप में मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत कई अन्य दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में नितिन नवीन ने मंगलवार, 20 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी या यूं कहें कि सबसे पहली चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव है। क्योंकि पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ ही नवीन के पास होने या फेल होने की चर्चाएं शुरू हो जाएंगी। दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी का जनाधार बढ़ाना और कर्नाटक में पार्टी को फिर से सत्ता में लाना भी उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। यह चुनौती उनके पहले दिन के फैसलों में भी साफ-साफ नजर आती है।

पार्टी अध्यक्ष का कार्यभार संभालते ही उन्होंने पहले दिन ही ताबड़तोड़ अंदाज में केरल, तेलंगाना, बेंगलुरू और चंडीगढ़ के लिए चुनाव प्रभारी और चुनाव सह प्रभारियों की नियुक्तियों कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। पहले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन को क्यों अपना बॉस बताया था, यह कुछ घंटे बाद ही साफ हो गया क्योंकि जिन नेताओं को नितिन नवीन के आदेश से नई जिम्मेदारी दी गई है,उसमें कई नाम बहुत ही चौंकाने वाले हैं।

नवीन ने अपने अध्यक्षीय कार्यकाल के पहले ही दिन, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही तावड़े को चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया है। तावड़े बिहार के प्रभारी भी हैं। तावड़े के साथ ही केरल में चुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। शोभा करंदलाजे कर्नाटक से सांसद हैं।

अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर जेपी नड्डा तक, केरल हमेशा से ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती रहा है। नवीन पहले दिन से ही इस अभियान में जुट गए हैं। दक्षिण भारत में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने की चुनौती में कर्नाटक भी शामिल हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का वह राज्य है, जहां सबसे पहले कमल खिला था लेकिन आज वहां कांग्रेस की सरकार है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि एक चौंकाने वाला फैसला करते हुए राम माधव जैसे दिग्गज नेता को ग्रेटर बेंगलुरु निगम चुनाव के लिए चुनाव प्रभारी बनाया गया है।राम माधव अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने के दौरान पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। राम माधव के साथ ही राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया और महाराष्ट्र के विधायक संजय उपाध्याय को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

तेलंगाना में होने वाले नगर निगम चुनावों को भी पूरी गंभीरता से लेते हुए नितिन नवीन ने पहले ही दिन तीन बड़े नेताओं को वहां की जिम्मेदारी थमा दी है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आशीष शेलार को वहां का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। शेलार नितिन नवीन के साथ काम कर चुके हैं, महाराष्ट्र युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी माने जाते हैं। उनके साथ ही राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी एवं हरियाणा से राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है।

इन नियुक्तियों से यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि बतौर युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को कर्नाटक, तेलंगाना , केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम जैसे राज्यों में चुनावी जीत हासिल कर, अपनी क्षमता को साबित करना ही होगा।

प्रेरणा

सेवा की सच्ची शक्ति

इतिहास के पन्नों में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका योगदान किसी एक घटना या समय तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वे मानव चेतना की दिशा ही बदल देते हैं। क्रीमिया युद्ध के दौरान फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कार्य ऐसा ही था। वह समय केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि मानव व्यवस्था की विफलता का भी था। रणभूमि पर गोलियाँ चल रही थीं, लेकिन उससे अधिक घातक हालात अस्पतालों के भीतर थे। गंदगी, संक्रमण, अव्यवस्थित देखभाल और उपेक्षा ने सैनिकों को भीतर से तोड़ दिया था। बीमार और घायल सैनिकों की मृत्यु को युद्ध की स्वाभाविक परिणति मान लिया गया था। यही सोच सबसे बड़ा संकट थी, क्योंकि जब पीड़ा को भाग्य मान लिया जाए, तब सुधार की इच्छा ही मर जाती है। जब फ्लोरेंस नाइटिंगेल वहां पहुँचीं, तो उन्होंने सबसे पहले इसी जड़ समस्या को पहचाना। उन्होंने देखा कि सैनिक केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उपेक्षित हैं। गंदे कमरों में पड़े सैनिकों के पास साफ पानी तक नहीं था, भोजन अनियमित और अस्वस्थ था, और देखभाल का कोई निश्चित ढांचा नहीं था। उस समय चिकित्सा ज्ञान सीमित था, लेकिन स्वच्छता और अनुशासन जैसी मूलभूत बातें भी नजरअंदाज की जा रही थीं। फ्लोरेंस ने समझ लिया कि यदि व्यवस्था नहीं बदली गई, तो दवाइयाँ भी व्यर्थ साबित होंगी।

उन्होंने किसी बड़े आदेश या शक्ति के सहारे नहीं, बल्कि अपने आचरण और संकल्प के बल पर परिवर्तन की शुरुआत की। रात में हाथ में दीपक लेकर वार्डों में घूमना केवल सहानुभूति का संकेत नहीं था, बल्कि यह विश्वास का संचार था। सैनिकों के लिए वह दीपक आशा की रोशनी बन गया। उन्हें लगने लगा कि कोई है जो उन्हें संख्या नहीं, मनुष्य मानता है। लेकिन फ्लोरेंस की करुणा भावुकता तक सीमित नहीं थी। उन्होंने साफ-सफाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, नालियों की सफाई करवाई, हवादार कमरों की व्यवस्था की, स्वच्छ बिस्तर और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित किया। यह सब उस समय क्रांतिकारी कदम माने जाते थे।

उनका सामना विरोध से भी हुआ। कई अधिकारी और कर्मचारी उन्हें अव्यावहारिक समझते थे। कुछ को लगता था कि युद्ध की परिस्थितियों में इतनी व्यवस्था संभव नहीं है, तो कुछ को उनका अनुशासन असहज लगता था। लेकिन फ्लोरेंस अपने उद्देश्य पर अडिग रहीं। उनके लिए सेवा का अर्थ केवल दया दिखाना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना था। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि अनुशासन कोई कठोरता नहीं, बल्कि जीवन की रक्षा का माध्यम है। धीरे-धीरे परिणाम सामने आने लगे। मृत्यु दर में आश्चर्यजनक रूप से कमी आई, बीमारियों का प्रसार रुका और सैनिकों का मनोबल बढ़ने लगा।

इस परिवर्तन ने सबको चकित कर दिया। जो अधिकारी पहले उन्हें संदेह की नजर से देखते थे, वही अब उनके निर्णयों को मानने लगे। अस्पतालों का वातावरण बदल गया। जहाँ पहले निराशा और मृत्यु का साया था, वहाँ अब आशा और उपचार का भाव दिखाई देने लगा। यह सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर श्रम, अनुशासन और करुणा के संतुलन से संभव हुआ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा तब प्रभावी होती है, जब उसमें व्यवस्था और संवेदना दोनों साथ चलें।

एक बार उनसे पूछा गया कि वे इतनी कठिन परिस्थितियों में भी थकती क्यों नहीं। उनका उत्तर सरल, लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा कि जब किसी का दर्द आपकी जिम्मेदारी बन जाता है, तब थकान पीछे हट जाती है। इस कथन में सेवा का वास्तविक दर्शन छिपा है। जब मनुष्य किसी कार्य को केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व मानता है, तब उसमें ऊर्जा स्वयं उत्पन्न हो जाती है। यह ऊर्जा बाहरी प्रोत्साहन से नहीं, भीतर के संकल्प से आती है। फ्लोरेंस की कहानी हमें आज के समय में भी बहुत कुछ सिखाती है। हम अक्सर सेवा को भावनात्मक सहानुभूति तक सीमित कर देते हैं। हम दुख देखकर द्रवित हो जाते हैं, लेकिन व्यवस्था सुधारने, कठिन निर्णय लेने और अनुशासन लागू करने से बचते हैं। दूसरी ओर, कहीं-कहीं नियम तो होते हैं, लेकिन उनमें मानवीय संवेदना का अभाव होता है। दोनों ही स्थितियाँ अधूरी हैं। सच्ची सेवा वही है, जिसमें करुणा मनुष्य को जोड़ती है और अनुशासन व्यवस्था को मजबूत करता है।

यह सिद्धांत केवल चिकित्सा या युद्ध तक सीमित नहीं है। समाज, शिक्षा, प्रशासन और परिवार—हर क्षेत्र में इसकी आवश्यकता है। एक शिक्षक जो छात्रों से प्रेम करता है, लेकिन उन्हें अनुशासन नहीं सिखाता, वह उनके भविष्य के साथ अन्याय करता है। वहीं, जो केवल नियमों पर जोर देता है और संवेदना को भूल जाता है, वह भय तो पैदा कर सकता है, प्रेरणा नहीं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने जीवन से यह संतुलन सिखाया।

उनका योगदान केवल उस युद्धकाल तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने नर्सिंग को एक सम्मानित और व्यवस्थित पेशा बनाया। उन्होंने यह दिखाया कि सेवा कोई निम्न कार्य नहीं, बल्कि उच्चतम मानवीय कर्तव्य है। उनका दीपक आज भी प्रतीक है—उस रोशनी का जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। हर वह व्यक्ति जो बिना दिखावे के जिम्मेदारी निभाता है, उसी दीपक की लौ को आगे बढ़ाता है। अंततः फ्लोरेंस नाइटिंगेल की कथा हमें यह समझाती है कि बड़े परिवर्तन हमेशा बड़े साधनों से नहीं होते। कई बार छोटे, लगातार किए गए सही काम ही इतिहास बदल देते हैं। साफ पानी, स्वच्छ वातावरण, नियमित देखभाल—ये साधारण कदम थे, लेकिन इन्हीं ने असंख्य जीवन बचाए। यही सेवा की सच्ची शक्ति है। जब करुणा को अनुशासन का आधार मिलता है, तब सेवा केवल सहायता नहीं, बल्कि समाज को नई दिशा देने वाला परिवर्तन बन जाती है।

बंगाल में वर्चस्व के लिए टीएमसी-भाजपा टकराव तेज

भारत के पूर्वी प्रांत बंगाल में सियासी महासंग्राम शुरू हो चुका है। विधानसभा चुनाव मार्च या अप्रैल में होंगे। पांच मई तक नई सरकार को शपथ लेनी होगी। ममता बनर्जी इस समय कई कारणों से सुर्खियों में हैं। ईडी से उनका टकराव हाल की बात है। उससे पहले उन्होंने एसआईआर के खिलाफ जबर्दस्त आवाज उठाई और चुनाव आयोग को धमकाया। इन हालातों के मध्यनजर सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और उन्हें शांत किया।

ईडी ने वहां के कोयला कारोबारी और एक एजेंसी आईपैक के दफ्तरों और अन्य ठिकानों पर मनी लॉन्डरिंग के मामले में छापा मारा। ममता दीदी स्वयं वहां पहुंच गईं और फाइलें, लैपटॉप वगैरह उठा ले गईं तथा अपने पुलिस वालों से कहकर ईडी अफसरों और कर्मियों पर एफआईआर तक करवा दी। एफआईआर करवाना उनका पुराना तरीका है ताकि प्रतिद्वंद्वी पर दबाव बना रहे।

अब मामला हाईकोर्ट और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में देश के सबसे बड़े दो वकील ममता दीदी की तरफ से खड़े हो गए। ईडी ने कोलकाता छापेमारी मामले में बंगाल पुलिस के कामकाज में दखलंदाजी के आरोपों के बीच बंगाल पुलिस के महानिदेशक को हटाने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट में ममता के वकीलों ने राज्य पुलिस द्वारा की गयी एफआईआर को न्यायसंगत बताया। न्यायाधीश ने नाराजगी जताई और कड़े शब्दों में कहा कि यह गंभीर विषय है कि राज्य पुलिस किसी वैधानिक केंद्रीय एजेंसी की कार्रवाई में हस्तक्षेप कर रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि संविधान हर संस्था को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार देता है और राज्य पुलिस को यह छूट नहीं है कि वह ईडी जैसी एजेंसियों के काम में बाधा डाले। कोर्ट ने साफ किया कि अंतिम फैसले तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी।

दूसरी ओर, ममता दीदी ने एसआईआर के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है, जहां से उन्हें डर है कि उनके समर्थकों के नाम ज्यादा संख्या में कट न जाएं। सभी जानते हैं कि बंगाल में घुसपैठ के चलते लाखों की तादाद में बांग्लादेशी मौजूद हैं। वे खुलेआम टीएमसी का समर्थन करते हैं और इसलिए पार्टी नहीं चाहती है कि उनके नाम कटें। इसके अलावा वहां रोहिंग्या भी बड़ी संख्या में आ घुसे हैं। उन्हें भी देश से भगाने की बात की जा रही है लेकिन ममता दीदी इसे स्वीकार नहीं करतीं।

कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बंगाल में पतन के बाद अब वहां एक दशक से लड़ाई भाजपा बनाम तृणमूल के बीच है। भाजपा ने पिछले दो चुनावों में काफी प्रयास किया, लेकिन वे टीएमसी की आक्रामक नीति और प्रशासन के सहयोग के सामने जीत का बिगुल नहीं बजा पाए। इस बार पार्टी नई रणनीति के साथ अमित शाह के नेतृत्व में उतरी है। उन्होंने बंगाल के चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। गृहमंत्री ने दिसंबर महीने में कोलकाता जाकर वहां पहले तो अपने पार्टी संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत की और फिर आरएसएस के कार्यकर्ताओं से मंत्रणा की। मकसद था कि दोनों संगठनों में सामंजस्य बना रहे। उन्होंने बहुत ही आक्रामक ढंग से शुरुआत की है और उसके बाद पीएम मोदी खुद ही बंगाल पहुंच गए। उन्होंने वहां के हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इतना ही नहीं, देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी बंगाल से ही शुरू की गई, जबकि राज्य को पहले ही लगभग आधा दर्जन अमृत भारत एक्सप्रेस सेवाएं मिल चुकी हैं। ये सभी कार्यक्रम वोटरों को आकर्षित करने की योजना का हिस्सा हैं।

भाजपा और अमित शाह की नीति रही है कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखा जाए। गृहमंत्री ने बंगाल में यही किया और उनसे हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के चुनींदा नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के साथ भी गहन बातचीत की। स्थिति की समीक्षा करने और रणनीति बनाने के लिए उन्होंने भाजपा के विधायकों, सांसदों के अलावा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभासदों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बंगाल, जो कभी देश का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, अब गिरावट के कारण 2023-24 में छठे स्थान पर पहुंच गया है। जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय में भी गिरावट आई है। यहां प्रति व्यक्ति औसत आय राष्ट्रीय आय से भी घटकर नीचे आ गई है।

तृणमूल कांग्रेस को सत्ता में आए 14 साल से ज्यादा समय हो चुका है। पार्टी ने राज्य से वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका, लेकिन उसके बाद यहां आपेक्षित विकास नहीं हुआ। कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई। बंगाल में बेरोजगारी दर बढ़ी है। राज्य में पलायन तेज हुआ है। राज्य के स्कूल-कॉलेज को टीएमसी ने राजनीति का गढ़ बना दिया है। साहित्य, कला-संस्कृति से संपन्न यह राज्य रंगत खो रहा है। बहरहाल, सत्तारूढ़ दल और मुख्य विपक्षी दल में तलवारें खिंच गई हैं।

अभियान

जब आस्था अग्नि को भी वश में कर लेती है

भारत की आध्यात्मिक परंपरा केवल पूजा-पाठ या कर्मकांड तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह अनुभव, साधना और रहस्य की ऐसी परतों को समेटे हुए है, जहाँ पहुँचकर मानवीय बुद्धि स्वयं को छोटा महसूस करने लगती है। असम की राजधानी गुवाहाटी में नीलाचल पर्वत पर स्थित मां कामाख्या का मंदिर इसी रहस्यात्मक चेतना का जीवंत उदाहरण है। यह मंदिर देवी सती के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है और शक्ति उपासना की तांत्रिक परंपरा में इसका स्थान सर्वोपरि है। यहां देवी को केवल माता के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा के रूप में पूजा जाता है। इसी कारण कामाख्या मंदिर की परंपराएं भी सामान्य धार्मिक स्थलों से अलग, गहन और कभी-कभी चमत्कारी प्रतीत होती हैं।

मां कामाख्या मंदिर से जुड़ी सबसे विलक्षण परंपराओं में से एक है यहां का विशेष प्रसाद, जिसे 'महानिर्मल्य' कहा जाता है। यह प्रसाद केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर व्यक्ति के मन में प्रश्न, विस्मय और श्रद्धा एक साथ जन्म लेते हैं। इस प्रसाद को तैयार करने और वितरित करने की प्रक्रिया साधारण नहीं है। मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी खौलते हुए तेल या घी में बिना किसी सुरक्षा के अपना हाथ डालते हैं और उसी में से प्रसाद निकालकर श्रद्धालुओं को वितरित करते हैं। यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से होता है, भक्त अपनी आंखों से देखते हैं कि तेल या घी उबल रहा है, उसमें बुलबुले उठ रहे हैं, फिर भी पुजारी के हाथ को कोई क्षति नहीं पहुँचती।

इस दृश्य को देखने वाले अधिकांश लोग पहली बार में इसे अपनी आंखों पर विश्वास न होने जैसा अनुभव बताते हैं। सामान्य ज्ञान के अनुसार खौलते तेल में हाथ डालना गंभीर जलन और घाव का कारण बन सकता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं होता। न तो पुजारी के हाथ पर छाले पड़ते हैं, न त्वचा झुलसती है और न ही जलन के कोई चिह्न दिखाई देते हैं। यह तथ्य ही इस परंपरा को रहस्यमय बनाता है। मंदिर से जुड़े लोग और श्रद्धालु इसे मां कामाख्या का साक्षात चमत्कार मानते हैं और विश्वास करते हैं कि यह देवी की कृपा के बिना संभव नहीं है।

कामाख्या मंदिर को तांत्रिक शक्तिपीठ माना जाता है। यहां साधना का स्वरूप भक्ति से अधिक साधना और ऊर्जा के जागरण से जुड़ा हुआ है। यह विश्वास किया जाता है कि मां कामाख्या सृष्टि की रचनात्मक शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यही कारण है कि यहां की उपासना में जीवन, सृजन और ऊर्जा को केंद्र में रखा जाता है। महानिर्मल्य का प्रसाद भी इसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो अग्नि जैसे तत्व पर भी विजय प्राप्त कर लेती है। श्रद्धालुओं का मानना है कि जब पुजारी मंत्रोच्चारण और विशेष पूजा के बाद खौलते तेल में हाथ डालते हैं, तब वे स्वयं नहीं रहते, बल्कि देवी की शक्ति का माध्यम बन जाते हैं। इस परंपरा के पीछे केवल क्षणिक आस्था नहीं, बल्कि वर्षों की कठोर साधना और अनुशासन छिपा हुआ है। जो पुजारी इस विशेष सेवा के लिए चुने जाते हैं, वे सामान्य जीवन नहीं जीते। माना जाता है कि वे पूरे वर्ष कठोर व्रत, संयम और तपस्या का पालन करते हैं। उनका खान-पान सात्त्विक होता है, उनका आचरण पवित्र माना जाता है और वे सांसारिक आकर्षणों से दूरी बनाए रखते हैं। तांत्रिक परंपरा में यह विश्वास गहराई से जुड़ा हुआ है कि जब साधक अपने भीतर के भय, अहंकार और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, तभी वह बाहरी तत्वों से प्रभावित होना बंद कर देता है।

मां कामाख्या मंदिर की इस परंपरा को लेकर समय-समय पर वैज्ञानिक और तार्किक प्रश्न भी उठते रहे हैं। कुछ लोग इसे मनोवैज्ञानिक प्रभाव, विशेष अभ्यास या किसी अज्ञात तकनीक से जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मंदिर प्रशासन और पुजारी वर्ग का कहना है कि यह कोई प्रदर्शन या प्रयोग नहीं है। यहां कोई सुरक्षा उपाय, रासायनिक लेप या छल नहीं होता। जो कुछ भी होता है, वह पूर्ण आस्था, मंत्र शक्ति और देवी की कृपा से होता है। यही कारण है कि इस परंपरा को लेकर मंदिर में कोई दिखावा नहीं किया जाता, न ही इसे प्रचार का साधन बनाया जाता है।

श्रद्धालुओं के लिए महानिर्मल्य का प्रसाद केवल खाने योग्य वस्तु नहीं, बल्कि देवी की ऊर्जा का अंश माना जाता है। लोग मानते हैं कि इस प्रसाद को ग्रहण करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, भय समाप्त होता है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। विशेष रूप से तांत्रिक साधना से जुड़े साधक इस प्रसाद को अत्यंत पवित्र मानते हैं और इसे देवी की सीधी कृपा का संकेत मानते हैं। कई भक्तों का यह भी विश्वास है कि यह प्रसाद रोग, संकट और मानसिक अशांति से रक्षा करता है।

इस परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां शक्ति को प्रदर्शन के रूप में नहीं देखा जाता। पुजारी स्वयं को किसी विशेष क्षमता का स्वामी नहीं मानते, बल्कि देवी का साधन मानते हैं। यही विनम्रता इस परंपरा की आत्मा है। माना जाता है कि यदि किसी पुजारी के मन में जरा भी अहंकार या संदेह उत्पन्न हो जाए, तो वह इस सेवा के योग्य नहीं रह जाता। इसीलिए यह कार्य केवल उन्हीं लोगों द्वारा किया जाता है, जो स्वयं को पूरी तरह मां कामाख्या के चरणों में समर्पित कर चुके होते हैं।

कामाख्या मंदिर की यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि आस्था कोई तात्कालिक भावना नहीं होती, बल्कि यह जीवनशैली बन जाती है। यहां आस्था अनुशासन से जुड़ी हुई है, संयम से जुड़ी हुई है और आत्मशुद्धि से जुड़ी हुई है। जब साधक भीतर से शुद्ध होता है, तब बाहरी तत्व उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। खौलते तेल में हाथ डालना इस आंतरिक विजय का प्रतीक बन जाता है, न कि केवल एक चमत्कारी दृश्य।

आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में, जहां हर चीज को प्रमाण और तर्क के तराजू पर तौला जाता है, वहां मां कामाख्या मंदिर जैसी परंपराएं यह याद दिलाती हैं कि जीवन में कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं, जिन्हें केवल अनुभव किया जा सकता है, पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। यह मंदिर विज्ञान और आस्था के बीच एक ऐसे सेतु की तरह खड़ा है, जहाँ दोनों अपनी सीमाएं पहचानते हैं। विज्ञान सवाल करता है, आस्था अनुभव कराती है, और दोनों के बीच मनुष्य अपनी चेतना का विस्तार करता है।

मां कामाख्या मंदिर की यह चमत्कारी परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और मर्यादा के साथ निभाई जा रही है। यहां आने वाला हर श्रद्धालु इस अनुभव को अपने साथ लेकर लौटता है। कोई इसे चमत्कार कहता है, कोई दिव्य शक्ति, तो कोई इसे साधना की पराकाष्ठा मानता है। लेकिन एक बात सभी स्वीकार करते हैं कि इस दृश्य के सामने खड़े होकर मन स्वतः नतमस्तक हो जाता है।

अंततः यह परंपरा हमें यही संदेश देती है कि जब आस्था पूर्ण होती है, जब समर्पण निष्कपट होता है और जब साधना अहंकार से मुक्त होती है, तब असंभव भी संभव हो जाता है। मां कामाख्या की कृपा से जुड़ा यह अनुभव केवल तेल और अग्नि पर विजय की कथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की आंतरिक शक्ति, विश्वास और समर्पण की कहानी है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि आस्था और रहस्य का जीवंत केंद्र बना हुआ है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004
(2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, "Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002
and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूती: रिटायर्ड सैन्य चालकों का मानदेय बढ़ाकर 30 हजार, सेवा अवधि में भी विस्तार

पटना। बिहार सरकार ने राज्य की पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम और व्यावहारिक फैसला लिया है। पुलिस विभाग में कार्यरत सेना से सेवानिवृत्त चालकों को अब पहले की तुलना में बेहतर आर्थिक सुरक्षा और स्थायित्व मिलेगा। सरकार ने इन चालकों का मासिक मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दिया है, साथ ही उनकी सेवा अवधि में एक वर्ष का विस्तार भी मंजूर किया है। यह निर्णय न केवल इन अनुभवी चालकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि राज्य की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को सुचारु और भरोसेमंद बनाए रखने की दिशा में भी एक मजबूत कदम माना जा रहा है।

बिहार में आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली, यानी ईआरएसएस-112, राज्य की कानून-व्यवस्था और नागरिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन चुकी है। किसी भी दुर्घटना, अपराध, स्वास्थ्य आपातस्थिति या आपदा के समय यही प्रणाली सबसे पहले सक्रिय होती है। ऐसे में इन आपातकालीन वाहनों को संचालित करने वाले चालकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इन्हीं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि सेना से सेवानिवृत्त, प्रशिक्षित और अनुशासित चालकों की सेवाओं को बनाए रखा जाए और उन्हें बेहतर मानदेय दिया जाए, ताकि वे पूरे मनोयोग से अपनी जिम्मेदारी निभा सकें।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि यह निर्णय पूरी तरह व्यावहारिक जरूरतों और जमीनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ईआरएसएस-112 के तहत तैनात पुलिस वाहनों का संचालन किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होना चाहिए। वर्तमान में नए चालकों की भर्ती और उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने की प्रक्रिया समय लेने वाली है। ऐसे में

जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक एडब्ल्यूपीओ दानापुर के माध्यम से नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त सैन्य चालकों की सेवाएं जारी रखना आवश्यक है। इन्हीं कारणों से सरकार ने उनकी सेवा अवधि में एक वर्ष का विस्तार देने का निर्णय लिया है।

सेना से सेवानिवृत्त चालक अपने लंबे अनुभव, अनुशासन और तकनीकी दक्षता के लिए जाने जाते हैं। कठिन परिस्थितियों में वाहन चलाने, तनावपूर्ण हालात में संयम बनाए रखने और समय की पाबंदी जैसे गुण इन चालकों को सामान्य चालकों से अलग बनाते हैं। यही कारण है कि आपातकालीन सेवाओं में इनकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस विभाग के अधिकारियों का भी मानना है कि इन चालकों के कारण ईआरएसएस-112 की प्रतिक्रिया क्षमता बेहतर हुई है और कई गंभीर मामलों में समय पर मदद पहुंचाना संभव हो पाया है।

सरकार के फैसले के तहत अब इन चालकों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा, जो पहले 25 हजार रुपये था। इसके अलावा उन्हें 4,000 रुपये का वार्षिक वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा। यह वर्दी भत्ता न केवल उनकी पहचान और अनुशासन को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें सम्मान का भी अहसास कराता है। राज्य सरकार का मानना है कि बेहतर आर्थिक प्रोत्साहन मिलने से इन चालकों का मनोबल बढ़ेगा और वे और अधिक समर्पण के साथ अपनी सेवाएं देंगे।

एक वर्ष के सेवा विस्तार और बढ़े हुए मानदेय पर सरकार को लगभग 161 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा। हालांकि, सरकार इसे खर्च नहीं बल्कि निवेश के रूप में देख रही है। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह राशि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था, नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए खर्च की जा रही है। उनका कहना है कि जब बात आम लोगों की सुरक्षा और त्वरित सहायता की हो, तो सरकार किसी भी जरूरी खर्च से पीछे नहीं हट सकती।

इस फैसले को राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनडीए सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि वह कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। हाल के वर्षों में बिहार में पुलिस आधुनिकीकरण, नए थानों की स्थापना, संसाधनों की उपलब्धता और तकनीकी उन्नयन पर जोर दिया गया है। रिटायर्ड सैन्य चालकों के मानदेय में बढ़ोतरी और सेवा विस्तार भी इसी व्यापक नीति का हिस्सा है।

आस्था, व्यवस्था और अनुशासन का संगम: वसंत पंचमी पर माघ मेले के लिए प्रयागराज तैयार

प्रयागराज। संगम की रेती पर आस्था का विराट प्रवाह एक बार फिर अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। माघ मेला 2026 के चौथे प्रमुख स्नान पर्व वसंत पंचमी को लेकर प्रयागराज पूरी तरह सतर्क और तैयार नजर आ रहा है। प्रशासन का अनुमान है कि अकेले वसंत पंचमी के दिन एक से डेढ़ करोड़ श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे, जबकि पंचमी से सप्तमी तक कुल स्नानार्थियों की संख्या करीब साढ़े तीन करोड़ तक पहुंच सकती है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ यह स्नान क्रम महाशिवरात्रि तक चलेगा और वसंत पंचमी के बाद अगला बड़ा स्नान पर्व माघी पूर्णिमा को पड़ेगा। ऐसे में माघ मेला प्रशासन के सामने चुनौती केवल श्रद्धालुओं की संख्या नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा, सुविधा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने की भी है।

हर वर्ष की तरह इस बार भी वसंत पंचमी को माघ मेले का अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मां सरस्वती की पूजा के साथ संगम स्नान का विशेष महत्व है। देश के कोने-कोने से साधु-संत, कल्पवासी, अखाड़ों के अनुयायी और सामान्य श्रद्धालु इस पावन अवसर पर प्रयागराज पहुंचते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले से ही मेला क्षेत्र में कल्पवास कर रहे हैं, जिससे स्नान पर्व के दिन भीड़ का दबाव और अधिक बढ़ जाता है। प्रशासन का आकलन है कि बाहरी जिलों और राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के कारण वसंत पंचमी के दिन मेला क्षेत्र और शहर दोनों पर भारी दबाव रहेगा।

इसी को ध्यान में रखते हुए माघ मेला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बार आठ स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है, जो मेला क्षेत्र से लेकर शहर की सीमाओं तक प्रभावी रहेगी। पुलिस, अर्धसैनिक बल, पीएसी, होमगार्ड और स्वयंसेवी संगठनों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। करीब पंद्रह हजार से अधिक पुलिस और सुरक्षाकर्मी मेला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं, जिनका उद्देश्य केवल सुरक्षा ही नहीं बल्कि भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की मदद करना भी है। घाटों, पांटून पुलों, प्रमुख मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है।

भीड़ नियंत्रण के लिए इस बार तकनीक का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे मेला क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी स्थान पर अचानक भीड़ बढ़ने की स्थिति में तत्काल सूचना संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके, इसके लिए एकीकृत संचार व्यवस्था बनाई गई है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे लगातार फील्ड में रहकर स्थिति का आकलन करें और जरूरत पड़ने पर तुरंत निर्णय लें।

यातायात प्रबंधन माघ मेले की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन और प्रस्थान को व्यवस्थित करना किसी भी प्रशासन के लिए आसान नहीं होता। इसे देखते हुए वसंत पंचमी के अवसर पर कई मार्गों को नो-व्हीकल जोन घोषित किया गया है। शहर के बाहरी इलाकों में पार्किंग स्थल बनाए गए हैं, जहां से श्रद्धालुओं को शटल सेवाओं और पैदल मार्गों के माध्यम से मेला क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा। प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग मार्ग निर्धारित किए गए हैं ताकि आमने-सामने की भीड़ न बने और भगदड़ जैसी स्थिति से बचा जा सके।

मेला क्षेत्र में कल्पवासियों और स्नानार्थियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। स्वच्छ पेयजल, शौचालय, स्नान घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। अस्थायी अस्पताल, एंबुलेंस और मेडिकल टीमों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा गया है। ठंड के मौसम को देखते हुए अलाव की व्यवस्था की गई है और जरूरतमंद श्रद्धालुओं के लिए कंबल वितरण की भी योजना बनाई गई है। प्रशासन का प्रयास है कि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो और वह सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण तरीके से स्नान और दर्शन कर सके।

धार्मिक दृष्टि से वसंत पंचमी का महत्व माघ मेले में विशेष रूप से देखा जाता है। अखाड़ों के साधु-संत इस दिन विशेष अनुष्ठान और स्नान करते हैं। इसके लिए अखाड़ों के साथ समन्वय बनाकर अलग-अलग समय स्लॉट और मार्ग तय किए गए हैं, ताकि आम श्रद्धालुओं और अखाड़ों के स्नान में टकराव न हो। प्रशासन और अखाड़ा परिषद के बीच लगातार संवाद बना हुआ है, जिससे परंपरा और व्यवस्था दोनों का संतुलन बना रहे।

मेला प्रशासन यह भी जानता है कि इतनी बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में होते हैं। इसलिए महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती, खोया-पाया केंद्र, सूचना सहायता केंद्र और स्वयंसेवकों की टीम सक्रिय रखी गई है। किसी के बिछड़ने या परेशानी में पड़ने पर तत्काल सहायता मिल सके, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर और सार्वजनिक घोषणाओं का सहारा लिया जा रहा है।

पंजाब में केजरीवाल और भगवंत मान सरकार की स्वास्थ्य गारंटी पूरी - इसुदान गढ़वी

- **अब पंजाब के 65 लाख परिवारों को बिना शर्त और बिना भेदभाव के 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा – इसुदान गढ़वी**
- **जिन शानदार व महंगे अस्पतालों में अमीर इलाज कराते हैं, अब वहां गरीब भी इलाज करा सकेगा – इसुदान गढ़वी**
- **"आप" के मुख्यमंत्री जनता के लिए हेल्थ कार्ड बना रहे हैं और इनके मुख्यमंत्री विदेश में सैर-सपाटा कर रहे – इसुदान गढ़वी**
- **देश के इतिहास में यह पहली ऐसी योजना है जो सच में सबके लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है – इसुदान गढ़वी**
- **मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य – इसुदान गढ़वी**
- **कांग्रेस में सीएम बनने के लिए सभी आपस में लड़ रहे हैं, इन पार्टियों को लूटने के लिए सिर्फ सत्ता चाहिए – इसुदान गढ़वी**
- **सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब को सुरक्षित भविष्य दे सकती है – इसुदान गढ़वी**
- **यह दुनिया की इकलौती स्कीम है जिसमें किडनी ट्रांसप्लांट, कैंसर और हृदय रोग का भी मुफ्त इलाज होगा – इसुदान गढ़वी**

(जीएनएस)। गुजरात/अहमदाबाद। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत सिंह मान की ओर से पंजाब को मुफ्त इलाज की दी गई गारंटी भी पूरी हो गई। इस अवसर पर, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने कहा कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दी गई मुफ्त इलाज की गारंटी अब पूरी तरह साकार हो चुकी है। अब पंजाब के हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सेहत योजना की शुरुआत के साथ ही पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है, जहां मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली और महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा एक साथ दी जा रही है।

जिन शानदार और महंगे निजी अस्पतालों में अब तक केवल अमीर लोग इलाज कराते थे, अब वहां गरीब किसान, मजदूर और रिक्शेवाला भी बिना पैसे के इलाज करा सकेगा। यह देश के इतिहास की पहली ऐसी योजना है, जो सच में सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देती है।

प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ कुछ मुख्यमंत्री अपने परिवारों के साथ विदेशों में घूम रहे हैं, दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री रात-दिन जनता के लिए हेल्थ कार्ड बनाने में लगे हैं। यही फर्क है उनकी सैर-सपाटे की राजनीति और आम आदमी पार्टी की सेवा की राजनीति में। कांग्रेस और अन्य दलों में मुख्यमंत्री बनने की होड़ मची हुई है। इन पार्टियों को जनता की नहीं, सिर्फ सत्ता की चिंता है ताकि वे लूट सकें। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पंजाब और पंजाबियों को सुरक्षित भविष्य दे सकती है।

उन्होंने कहा कि पिछले 75 वर्षों में कई सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी ने जनता की असली

चिंता नहीं की। आज जो ऐतिहासिक काम पंजाब में हो रहा है, वह आज़ादी के बाद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यह दौर पंजाब के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा।

चुनावी वादों का जिक्र करते हुए इसुदान गढ़वी ने कहा कि 'केजरीवाल की गारंटी' को मज़ाक समझने वाले आज देख रहे हैं कि मुफ्त बिजली, मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज सब कुछ संभव है। सरकार ने न केवल वादे पूरे किए, बल्कि स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह बदल दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में बीते चार वर्षों में 1000 से अधिक मोहल्ला क्लीनिक बनाए गए हैं, 500 और बन रहे हैं और अगले चार-पांच महीनों के अंदर हर गांव में 2500 'पिंड क्लीनिक' बनने वाले हैं। जो काम पिछली सरकारों ने 75 साल में किया, उससे शायद 10 गुना काम इस सरकार ने 4 साल में करके दिखा दिया है।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि अब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी नहीं है, मशीनें चालू हैं, मुफ्त दवाइयां मिल रही हैं और सरकारी अस्पताल निजी अस्पतालों से बेहतर बनते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना उन किसानों और मजदूरों के लिए वरदान है, जिन्हें बीमारी में अपनी ज़मीन, गहने और घर बेचने पड़ते थे। अब किसी को इलाज के लिए कर्ज़ या ज़मीन गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने बताया कि यह 10 लाख रुपये का बीमा सभी 65 लाख परिवारों के लिए है – अमीर-गरीब, सभी धर्मों और जातियों के लिए, बिना किसी शर्त के। न कोई कार्ड का रंग, न कोई भेदभाव। बस हेल्थ कार्ड दिखाइए और इलाज पाइए।

उन्होंने नशे और अपराध के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि पहली बार किसी सरकार ने नशा तस्करों और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई है। जब पंजाब के बच्चे नशे से मर रहे थे, तब विपक्ष को मानवाधिकार याद नहीं आए। आज अपराधियों पर कार्रवाई होने पर ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं।

इसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी कोई अमीरों की पार्टी नहीं है। यह कुदरत का करिश्मा है कि आम लोगों की यह पार्टी सत्ता में आई और जनता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस योजना का भी विरोध करेगा, लेकिन यह योजना सबके लिए है – "आप" सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया और न ऐसी कोई शर्त ही रखी कि कांग्रेसियों या अकालियों का इलाज नहीं होगा। सबका इलाज होगा, भगवान सबको खुश रखे।

अंत में इसुदान गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भारत देश के परिवारों के भविष्य की चिंता करती है। हमें सत्ता नहीं, सेवा चाहिए। जनता का विश्वास और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

एमसीएक्स पर सोना वायदा 1272 रुपये, चांदी वायदा 10190 रुपये और क्रूड ऑयल वायदा 89 रुपये लुढ़का

(जीएनएस)। मुंबईः देश के अग्रणी कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज एमसीएक्स पर कमोडिटी वायदा, ऑप्शंस और इंडेक्स फ्यूचर्स में 346944.33 करोड़ रुपये का टर्नओवर दर्ज हुआ। कमोडिटी वायदाओं में 96389.85 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ, जबकि कमोडिटी ऑप्शंस में 250535.62 करोड़ रुपये का नॉशनल टर्नओवर हुआ। बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स का जनवरी वायदा 41400 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था। कमोडिटी ऑप्शंस में कुल प्रीमियम टर्नओवर 7221.34 करोड़ रुपये का हुआ।

कीमती धातुओं में सोना-चांदी के वायदाओं में 82052.01 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। एमसीएक्स सोना फरवरी वायदा 151557 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 153784 रुपये और नीचे में 148777 रुपये पर पहुंचकर, 152862 रुपये के पिछले बंद के सामने 1272 रुपये या 0.83 फीसदी गिरकर 151590 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंचा। गोल्ड-गिनी जनवरी वायदा 2720 रुपये या 2.11 फीसदी औंधकर 126300 रुपये प्रति 8 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-पेटल जनवरी वायदा 392 रुपये या 2.44 फीसदी औंधकर 15666 रुपये प्रति 1 ग्राम पर आ गया। सोना-मिनी फरवरी वायदा 152347 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 154067 रुपये और नीचे में 148741 रुपये पर पहुंचकर, 1641 रुपये या 1.07 फीसदी औंधकर 151700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। गोल्ड-टेन जनवरी वायदा प्रति 10 ग्राम 152804 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 156144 रुपये और नीचे में 149951 रुपये पर पहुंचकर, 154588 रुपये के पिछले बंद के सामने 1984 रुपये या 1.28 फीसदी औंधकर 152604 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।

चांदी के वायदाओं में चांदी मार्च वायदा 319843 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 325602 रुपये और नीचे में 305449 रुपये पर पहुंचकर, 318492 रुपये के पिछले बंद के सामने 10190 रुपये या 3.2 फीसदी घटकर 308302 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इनके अलावा चांदी-मिनी फरवरी वायदा 10264 रुपये या 3.18 फीसदी लुढ़ककर 312699 रुपये प्रति किलो बोला गया। जबकि चांदी-माइक्रो फरवरी वायदा 10089 रुपये या 3.12 फीसदी औंधकर 312873 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

कमोडिटी वायदाओं में 96389.85 करोड़ रुपये और कमोडिटी ऑप्शंस में 250535.62 करोड़ रुपये का दर्ज हुआ टर्नओवर: सोना-चांदी के वायदाओं में 82052.01 करोड़ रुपये का हुआ कारोबार: बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स फ्यूचर्स 41400 पॉइंट के स्तर पर

मेटल वर्ग में 6080.74 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। तांबा जनवरी वायदा 25.1 रुपये या 1.96 फीसदी गिरकर 1254.75 रुपये प्रति किलो हुआ। जबकि जस्ता जनवरी वायदा 55 पैसे या 0.18 फीसदी की नरमी के साथ 311.35 रुपये प्रति किलो के भाव पर ट्रेड हो रहा था। इसके सामने एल्यूमीनियम जनवरी वायदा 1.05 रुपये या 0.33 फीसदी औंधकर 314 रुपये प्रति किलो पर आ गया। जबकि सीसा जनवरी वायदा 65 पैसे या 0.34 फीसदी की नरमी के साथ 190.3 रुपये प्रति किलो पर आ गया।

इन जिंसों के अलावा कारोबारियों ने एनर्जी सेगमेंट में 8249.80 करोड़ रुपये के सौदे किए। एमसीएक्स क्रूड ऑयल फरवरी वायदा सत्र के आरंभ में 5590 रुपये के भाव पर खूलकर, 5600 रुपये के दिन के उच्च और 5469 रुपये के नीचले स्तर को छूकर, 89 रुपये या 1.6 फीसदी गिरकर 5480 रुपये प्रति बैरल हुआ। जबकि क्रूड ऑयल-मिनी फरवरी वायदा 88 रुपये या 1.58 फीसदी गिरकर 5481 रुपये प्रति बैरल के भाव पर पहुंचा। इनके अलावा नैचुरल गैस जनवरी वायदा 456 रुपये पर खूलकर, ऊपर में 504.7 रुपये और नीचे में 456 रुपये पर पहुंचकर, 438.9 रुपये के पिछले बंद के सामने 65.8 रुपये या 14.99 फीसदी बढ़कर 504.7 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। जबकि नैचुरल गैस-मिनी जनवरी वायदा 65.8 रुपये या 14.98 फीसदी बढ़कर 505 रुपये प्रति एमएमबीटीयू के भाव पर ट्रेड हो रहा था। कृषि जिंसों में मेंथा ऑयल जनवरी वायदा सत्र के आरंभ में 950.3 रुपये के भाव पर खूलकर, 30 पैसे या 0.03 फीसदी के सुधार के साथ 959 रुपये प्रति किलो बोला गया।

कारोबार की दृष्टि से एमसीएक्स पर सोना के विभिन्न अनुबंधों में 43794.21 करोड़ रुपये और चांदी के विभिन्न अनुबंधों में 38257.79 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। इसके अलावा तांबा के वायदाओं में 5461.18 करोड़ रुपये, एल्यूमीनियम और एल्यूमीनियम-मिनी के वायदाओं में 286.89 करोड़ रुपये, सीसा और सीसा-मिनी के वायदाओं में 33.79 करोड़ रुपये, जस्ता और जस्ता-मिनी के वायदाओं में 292.06 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

इन जिंसों के अलावा क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल-मिनी के वायदाओं में 602.16 करोड़ रुपये के ट्रेड दर्ज हुए। जबकि नैचुरल गैस और नैचुरल गैस-मिनी के वायदाओं में 7639.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। मेंथा ऑयल के वायदा में 6.11 करोड़ रुपये की खरीद बेच की गई। जबकि कॉटन केंडी के वायदाओं में 0.13 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ।

ओपन इंटरेस्ट सोना के वायदाओं में 19175 लोट, सोना-मिनी के वायदाओं में 92440 लोट, गोल्ड-गिनी के वायदाओं में 31381 लोट, गोल्ड-पेटल के वायदाओं में 426384 लोट और गोल्ड-टेन के वायदाओं में 61177 लोट के स्तर पर था। जबकि चांदी के वायदाओं में 13982 लोट, चांदी-मिनी के वायदाओं में 37665 लोट और चांदी-माइक्रो वायदाओं में 106482 लोट के स्तर पर था। क्रूड ऑयल के वायदाओं में 17686 लोट और नैचुरल गैस के वायदाओं में 26943 लोट के स्तर पर था।

इंडेक्स फ्यूचर्स में बुलडेक्स जनवरी वायदा 41898 पॉइंट पर खूलकर, 41998 के उच्च और 40905 के नीचले स्तर को छूकर, 766 पॉइंट घटकर 41400 पॉइंट के स्तर पर ट्रेड हो रहा था।

कमोडिटी ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में क्रूड ऑयल फरवरी 5600 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति बैरल 39 रुपये की गिरावट के साथ 201.4 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 525 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 11.7 रुपये की बढ़त के साथ 15 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 155000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 985 रुपये की गिरावट के साथ 1369 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 320000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5784.5 रुपये की गिरावट के साथ 7630 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 5.07 रुपये की गिरावट के साथ 1.26 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 320 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन प्रति किलो 28 पैसे की नरमी के साथ 0.32 रुपये हुआ।

पुट ऑप्शंस में क्रूड ऑयल फरवरी 5500 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति बैरल 41 रुपये की बढ़त के साथ 257.6 रुपये हुआ। जबकि नैचुरल गैस जनवरी 450 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति एमएमबीटीयू 25.4 रुपये की गिरावट के साथ 3.4 रुपये हुआ।

सोना जनवरी 150000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति 10 ग्राम 474.5 रुपये की बढ़त के साथ 1946.5 रुपये हुआ। इसके सामने चांदी जनवरी 300000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 2295 रुपये की बढ़त के साथ 7777 रुपये हुआ। तांबा जनवरी 1250 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 4.78 रुपये की बढ़त के साथ 7.78 रुपये हुआ। जस्ता जनवरी 300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन प्रति किलो 29 पैसे की नरमी के साथ 0.02 रुपये हुआ।

पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक द्वारा महुवा-धोला रेल खण्ड तथा भावनगर वर्कशॉप का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक श्री विवेक कुमार गुप्ता ने 22 जनवरी, 2026 (गुरूवार) को भावनगर मंडल के महुवा-धोला रेल खण्ड तथा भावनगर परा स्थित ब्राडगेज वर्कशॉप का वार्षिक संरक्षा निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रेलखंड में संरक्षा एवं सुरक्षा मानकों, ढांचागत विकास कार्यों, यात्री सुविधाओं, कर्मचारियों हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा अन्य प्रगति कार्यों का विस्तृत एवं सूक्ष्म मूल्यांकन किया। महाप्रबंधक के साथ विभिन्न विभागों के प्रमुख विभागाध्यक्ष, भावनगर मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा, अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

अपने वार्षिक संरक्षा निरीक्षण के दौरान श्री गुप्ता ने लेवल क्रॉसिंग, महत्त्वपूर्ण बड़े एवं छोटे पुलों, अंडरब्रिज, सेक्शनल स्पीड ट्रायल, पॉइंट एवं क्रॉसिंग सहित विभिन्न संरक्षा तत्वों का गहन निरीक्षण किया तथा उन्होंने महुवा, सावरकुंडला एवं धोला स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का भी विस्तृत जायजा लिया।

महुवा में उन्होंने रेलवे स्टेशन के अलावा लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर एवं चल टिकट निरीक्षक रनिंग रूम, सोलर इंस्टॉलेशन, रेलवे कॉलोनी इत्यादि का संरक्षा निरीक्षण किया। सावरकुंडला में इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़े ओवरहेड इक्विपमेंट डिपो का निरीक्षण किया। इस सेक्शन में श्री गुप्ता ने रेलवे स्टेशन के अलावा लॉबी, रेलवे कॉलोनी तथा हेल्थ यूनिट का निरीक्षण किया। लीलीया मोटा-धोला खण्ड के बीच 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड ट्रायल रन किया गया। उन्होंने धोला में कॉलोनी, हेल्थ यूनिट का निरीक्षण किया । भावनगर परा स्थित ब्रॉडगेज वर्कशॉप में उन्होंने कोच सेक्शन, व्हील शॉप, एयर ब्रेक शॉप, नए बने हेरिटेज गैलरी इत्यादि का संरक्षा निरीक्षण किया। इसके साथ उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की।

इस अवसर पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। अमरेली के माननीय सांसद श्री भरतभाई सुतरिया एवं माननीय विधायक-सावरकुंडला श्री महेशभाई लालजीभाई कसवाला एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ सावरकुंडला रेलवे स्टेशन पर महाप्रबंधक की शुभेच्छा मुलाकात हुई। इसके अलावा महुवा, सावरकुंडला, धोला एवं भावनगर परा में ट्रेड यूनियन, चेम्बर ओफ कॉमर्स, सरपंच इत्यादि ने महाप्रबंधक के साथ मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

महाप्रबंधक ने यात्री सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए संबंधित अधिकारियों को ट्रैक, समपार फाटकों तथा अन्य संरक्षा मानकों की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए, ताकि ट्रेन सेवाएँ अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय और समयानुसार संचालित की जा सकें।

भारत के कौशल भविष्य को वैश्विक उड़ान देने की दिशा में बड़ा कदम

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत में कौशल विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने और उसे वैश्विक मंच से जोड़ने की दिशा में एक अहम पहल सामने आई है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और विश्व आर्थिक मंच के बीच हुआ ताजा समझौता केवल एक औपचारिक करार नहीं, बल्कि देश के युवा कार्यबल को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करने की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इस साझेदारी का मूल उद्देश्य भारत की व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालना और उसे तेजी से बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। आने वाले वर्षों में करोड़ों युवा कार्यबल में प्रवेश करने वाले हैं। यह स्थिति अवसर भी है और चुनौती भी। अवसर इसलिए कि सही कौशल और प्रशिक्षण के साथ यह युवा शक्ति भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में अग्रणी बना सकती है, और चुनौती इसलिए कि यदि यह कार्यबल आधुनिक तकनीक, उद्योग की जरूरतों और वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रशिक्षित नहीं हुआ, तो बेरोजगारी और कौशल-असंतुलन जैसी समस्याएं गहराती चली जाएंगी। ऐसे समय में एमएसडीई और डब्ल्यूईएफ के बीच हुआ यह समझौता नीति और क्रियान्वयन, दोनों स्तरों पर एक दूरदर्शी कदम माना जा रहा है।

इस समझौते के तहत भारत में 'स्किल्स एक्सीलरेटर' की स्थापना और उसके प्रभावी क्रियान्वयन की योजना है। इसका मतलब यह है कि कौशल विकास कार्यक्रम अब केवल सर्टिफिकेट तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें उद्योग की वास्तविक मांग, तकनीकी बदलाव और वैश्विक रोजगार बाजार की जरूरतों से सीधे जोड़ा जाएगा। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था को इस तरह तैयार किया जाएगा कि वह सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की चुनौतियों का सामना कर सके। डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्रीन जॉब्स, डेटा एनालिटिक्स और उभरते क्षेत्रों में कौशल निर्माण पर विशेष ध्यान दिए जाने की संभावना है।

विश्व आर्थिक मंच की भागीदारी इस पहल को वैश्विक अनुभव और विशेषज्ञता से समृद्ध करती है। डब्ल्यूईएफ वर्षों से दुनिया भर में सरकारों, उद्योग जगत और शैक्षणिक संस्थानों के साथ मिलकर भविष्य की नौकरियों, कौशल अंतर और कार्यबल के बदलाव पर काम करता रहा है। भारत के साथ यह साझेदारी न केवल वैश्विक सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं को अपनाने का अवसर देगी, बल्कि भारतीय मॉडल को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगी। इससे भारत की कौशल नीति एकतरफा नहीं रहेगी, बल्कि वैश्विक संवाद और सहयोग का हिस्सा बनेगी।

कौशल विकास एवं उद्यमिता के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी का यह कहना कि भारत का कौशल तंत्र अब भविष्य की कार्य-आवश्यकताओं के अनुरूप वैश्विक सहयोग के साथ संगठित रूप ले चुका है, इस पहल की गंभीरता को दर्शाता है। उनका बयान इस बात का संकेत है कि सरकार कौशल विकास को केवल सामाजिक योजना नहीं, बल्कि आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का आधार मान रही है। आज जब दुनिया भर में नौकरियों की प्रकृति तेजी से बदल रही है, तब भारत का समय से पहले इस दिशा में कदम बढ़ाना उसकी दूरदर्शिता को दिखाता है।

इस समझौते का एक अहम पहलू यह भी है कि इससे शिक्षा, प्रशिक्षण और उद्योग के बीच लंबे समय से चली आ रही दूरी को पाटने में मदद मिलेगी। अक्सर देखा गया है कि डिग्री और डिप्लोमा रखने के बावजूद युवाओं में उद्योग के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल की कमी रह जाती है। स्किल्स एक्सीलरेटर के माध्यम से पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पद्धतियों और मूल्यांकन प्रणाली को अधिक व्यावहारिक, लचीला और उद्योग-संगत बनाया जा सकता है। इससे न केवल रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी, बल्कि उद्यमिता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

वैश्विक स्तर पर देखें तो कई देश अपने कार्यबल को भविष्य के लिए तैयार करने में पीछे छूट रहे हैं। ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन के कारण पारंपरिक नौकरियां खत्म हो रही हैं और नई तरह की नौकरियां उभर रही हैं। ऐसे में भारत के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वह केवल सस्ते श्रम का केंद्र न बने, बल्कि कुशल और उच्च मूल्य वाले कार्यबल के रूप में अपनी पहचान बनाए। एमएसडीई और डब्ल्यूईएफ की यह साझेदारी इसी दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जिलों के प्रशासनिक तंत्र को स्थानीय प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेकर समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए स्पष्ट निर्देश दिए

- जनवरी - 2026 के राज्य स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में 110 प्रस्तुतियां, जिला स्वागत कार्यक्रम में 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रम में 2,565 सहित कुल 4,057 प्रस्तुतियों पर कार्रवाई की गई
- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल की किसानों और सामान्य नागरिक परिवारों की समस्याओं के समाधान के प्रति विशिष्ट संवेदनशीलता
- डभोई नगरपालिका के गटर के पानी के कारण किसानों की लगभग 150 बीघा कृषि योग्य भूमि को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए तात्कालिक रूप से सायफन बनाने के आदेश दिए
- बोटाद जिले में गांव के तालाब की पाल की अधिक ऊंचाई के कारण डूब में जा रही किसानों की 500 बीघा भूमि तथा आवागमन के रास्ते के संबंध में त्वरित समाधान के निर्देश
- सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के गिराए गए जर्जर मकानों के स्थान पर नए मकानों के शीघ्र निर्माण के लिए गुजरात हाउसिंग बोर्ड को दिशानिर्देश

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी-2026 के राज्य स्वागत में आई प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष रूप से सुनकर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण, ड्रेनेज और नालों में किए गए अवैध अतिक्रमण, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर किए गए अतिक्रमण से संबंधित राज्य स्वागत कार्यक्रम की प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।

हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित 'स्वागत ऑनलाइन' जन शिकायत निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जनवरी-2026 के राज्य-स्वागत में राज्य भर से 110 से अधिक प्रस्तुतिकर्ता अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, जिला स्वागत कार्यक्रम की 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रमकी 2,565 प्रस्तुतियों/प्रश्नों के संदर्भ में भी जिला एवं तहसील स्तर पर समाधान की कार्रवाई की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के समक्ष इस राज्य स्वागत कार्यक्रम में डभोई तथा बोटाद जिलों के किसानों द्वारा की गई प्रस्तुतियों तथा सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रश्न की प्रस्तुति पर उन्होंने त्वरित एवं संवेदनशील प्रतिसाद दिया।

मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिए कि डभोई नगरपालिका के गटर के पानी के कारण 33 किसानों की लगभग 150 बीघा कृषि योग्य भूमि की फसलों को नुकसान

न हो तथा भूमि खराब न हो, इसके लिए तात्कालिक रूप से सायफन बनाने और नगरपालिका का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) सुचारु रूप से कार्य करे तथा किसानों की इस दीर्घकालीन समस्या का समाधान हो।

मुख्यमंत्री के समक्ष बोटाद जिले के किसानों ने यह प्रस्तुति रखी कि गांव के तालाब की पाल की ऊंचाई बढ़ाने के परिणामस्वरूप 42 किसानों की लगभग 500 बीघा भूमि डूब में चली जाती है तथा खेतों में आवागमन का मार्ग बंद हो गया है। श्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत किसान हितोन्मुखी निर्णय लेकर इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए।

राज्य स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों के इन प्रश्नों के अतिरिक्त, सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जिन जर्जर मकानों को गिरा दिया गया है, उनके स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रस्तुति भी लाभार्थियों द्वारा की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों के संदर्भ में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को नए आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने के दिशानिर्देश भी दिए।

जनवरी -2026 के इस राज्य स्वागत में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री संजीव कुमार, अपर प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, सचिव श्री अजय कुमार, विशेष कार्याधिकारी श्री डी. के. पारेख, श्री राकेश व्यास तथा संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी पर हुए अत्याचार मामले में AAP प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी की प्रतिक्रिया

- शंकराचार्य पर हुआ अत्याचार BJP द्वारा हिंदू समाज और सनातन धर्म के अपमान के समान : इसुदान गढ़वी
- हिंदू समाज और आम आदमी पार्टी शंकराचार्य पर हुए हमले का समर्थन नहीं करती : इसुदान गढ़वी
- भाजपा हिंदुत्व के नाम पर सरकारी तंत्र द्वारा हिंसा और दबाव करती है : इसुदान गढ़वी
- शंकराचार्य के सम्मान के लिए आम आदमी पार्टी की कानूनी कार्रवाई की मांग : इसुदान गढ़वी
- भाजपा पार्टी नहीं, सर्टिफिकेट बेचने वाली कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है : इसुदान गढ़वी
- शंकराचार्य को स्नान करने से रोकना सनातन परंपरा का अपमान : इसुदान गढ़वी
- शंकराचार्य पर हुए अत्याचार मुद्दे पर RSS-VHP-बजरंग दल से आवाज उठाने की इसुदान गढ़वी की अपील

(जीएनएस)। अहमदाबाद/गुजरात। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी पर हुए अत्याचार मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा पार्टी नहीं, एक कॉर्पोरेट कंपनी है और सबको सर्टिफिकेट बेचने का ठेका ले लिया है। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान गत 18/01/2026 को जगद्गुरु शंकराचार्य श्री अविमुक्तेश्वरानंदजी और उनके शिष्यों पर हुआ अत्याचार हिंदू समाज और सनातन धर्म के लिए चिंता का विषय है। पुलिस और प्रशासन द्वारा शंकराचार्य और उनके शिष्यों को स्नान करने से रोका गया, पालकी रोकी गई, तथा उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर जो अत्याचार किया गया है, उससे सभी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शंकराचार्य और उनके शिष्यों के साथ हुआ यह अत्याचार केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि हिंदू समाज और सनातन परंपरा के सर्वमान्य मूल्यों पर किया गया घोर प्रहार है। भाजपा अब हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के नाम पर एक कॉर्पोरेट कंपनी बन गई है। भाजपा गायमाता, हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं से खेलने लगी है। शंकराचार्य से भी हिंदू आस्था का सर्टिफिकेट मांगते हैं ? आप कौन हैं? आप अपने राष्ट्रवाद का प्रमाण पत्र दें। आम आदमी पार्टी ने शंकराचार्य के समर्थन में विभिन्न जगहों पर विरोध दर्ज कराया है।

AAP नेता इसुदान गढ़वी ने आगे कहा कि RSS, बजरंग दल, VHP से मैं निवेदन करता हूं कि हमारे शंकराचार्यों पर भाजपा अत्याचार कर रही है, तब आपको भी एकजुट होकर इस शंकराचार्यजी के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए। आज एक शंकराचार्य हैं, कल दूसरे आएंगे, फिर हम सभी को भी हिंदुओं का प्रमाणपत्र देना पड़ेगा। यह केवल शंकराचार्य पर नहीं, हमारी हिंदू आस्था पर ठेस पहुंची है, आने वाली पीढ़ी पर भी ठेस पहुंची है। सभी सामाजिक संगठनों, साधु-संतों, कलाकारों, सनातन धर्म मानने वाले सभी से निवेदन करता हूं कि शंकराचार्यजी के समर्थन में हम सभी आवाज उठाएं।

फियो के अध्यक्ष श्री एस सी रल्हन की फियो के यूनियन बजट 2026 की सिफारिशें

(जीएनएस)। 1.कॉस्ट और कॉम्पिटिटिवनेस के मुद्दों पर ध्यान दें

प्रस्तावः बजट में इनवर्टेड कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, जहाँ कच्चे माल, कंपोनेंट्स या इंटरमीडिएट्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी तैयार माल की तुलना में ज़्यादा होती है। फियो निर्यात पर ध्यान देने वाली इंडस्ट्रीज़ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्य इनपुट पर इम्पोर्ट ड्यूटी को रैशनलाइज़ करने और कम करने की सिफारिश करता है ताकि इनपुट कॉस्ट तैयार प्रोडक्ट ड्यूटी के साथ अलाइन हो जाए।

औचित्यः एक इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भारतीय निर्यातकों की कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस को काफी कम कर देता है और जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट के ज़रिए कम वर्किंग कैपिटल को लॉक कर देता है। कई सेक्टर्स को इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, सिंथेटिक यार्न और फाइबर पर तैयार फैब्रिक और गारमेंट्स की तुलना में ज़्यादा कस्टम ड्यूटी लगती है, जिससे टेक्सटाइल और अपैरल वैल्यू चेन पर बुरा असर पड़ता है। इसी तरह, पीसीबी, कनेक्टर और सब-असेंबली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पर इम्पोर्टेड तैयार इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की तुलना में ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ावा नहीं मिलता। केमिकल और प्लास्टिक सेक्टर में, बेसिक रॉ केमिकल और पॉलीमर पर अक्सर डाउनस्ट्रीम फिनिश्ड प्रोडक्ट के मुकाबले ज़्यादा ड्यूटी लगती है, जिससे इंडियन मैन्युफैक्चरर को नुकसान होता है। लेदर और फुटवियर सेक्टर को भी इम्पोर्टेड फिनिश्ड फुटवियर के मुकाबले कंपोनेंट और एक्सेसरीज़ जैसे इनपुट पर ज़्यादा ड्यूटी का सामना करना पड़ता है। रॉ मटीरियल पर ड्यूटी कम करके या रीस्ट्रक्चर करके इन गड़बड़ियों को ठीक करने से प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी, वर्किंग कैपिटल का दबाव कम होगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इंडिया की एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मज़बूत होगी।

2.शिपिंग सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में इंडियन ग्लोबल-स्केल शिपिंग लाइनों के डेवलपमेंट के लिए टारगेटेड पॉलिसी और फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए, जिसमें लॉन्ग-टर्म फाइनेंस तक एक्सेस, वायबिलिटी गैप फंडिंग और सपोर्टिव रेगुलेटरी उपाय शामिल हैं।

औचित्यः फॉरेन शिपिंग लाइनों पर इंडिया की भारी डिपेंडेंस एक्सपोर्टर्स को ज़्यादा फ्रेट कॉस्ट, सप्लाई में रुकावट और ग्लोबल शिपिंग रेट में उतार-चढ़ाव का सामना कराती है। मज़बूत इंडियन शिपिंग कैरियर की कमी इंडिया की ट्रेड रेजिलिएंस और बारगेनिंग पावर को कमज़ोर करती है। इंडियन शिपिंग लाइनों को डेवलप करने से फ्रेट कॉस्ट काफी कम हो सकती है, रिलायबिलिटी बेहतर हो सकती है और लॉजिस्टिक्स पर स्ट्रेटेजिक कंट्रोल पक्का हो सकता है। अनुमान है कि भारत एक मज़बूत घरेलू शिपिंग इकोसिस्टम के ज़रिए माल ढुलाई में सालाना USD 40-50 बिलियन बचा सकता है। इससे सीधे तौर पर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और भारत के लंबे समय के ट्रेड और लॉजिस्टिक्स सिक्योरिटी को सपोर्ट मिलेगा।

3.फिस्कल और टैक्स इंसेंटिव – अनुसंधान एवं विकास सपोर्ट

प्रस्तावः फियो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 35(2एबी) के तहत इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास खर्च के लिए 200-250% वेटेड टैक्स डिडक्शन को फिर से शुरू करने और कंपनियों से आगे बढ़कर एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप, खासकर एमएसएमई को भी शामिल करने की सिफारिश करता है।

औचित्यः पहले, 200% वेटेड डिडक्शन ने अनुसंधान एवं विकास और इनोवेशन में प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को काफी बढ़ावा दिया है। इसके धीरे-धीरे कम होने से भारत का इनोवेशन इकोसिस्टम ऐसे समय में कमज़ोर हुआ है जब ग्लोबल कॉम्पिटिशन तेज़ हो रहा है। अभी, 38 ओईसीडी देशों में से 35 अनुसंधान एवं विकास के लिए टैक्स इंसेंटिव देते हैं, जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को नुकसान होता है। 200% डिडक्शन देने से प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस से जुड़े इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा। नॉन-कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को एलिजिबिलिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमएसएमई भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम की रीढ़ हैं और अक्सर बिना फिस्कल सपोर्ट के अनुसंधान एवं विकास में इन्वेस्ट करने की फाइनेंशियल कैपेसिटी की कमी होती है।

4.ओवरसीज़ मार्केटिंग के लिए टैक्स सपोर्ट

प्रस्तावः बजट में ओवरसीज़ मार्केटिंग, ब्रांडिंग, ट्रेड फेयर, बायर मीट और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पर होने वाले खर्च के लिए 200% टैक्स डिडक्शन देना चाहिए, जिससे खासकर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को फायदा हो।

औचित्यः कॉम्पिटिशन करने वाले एक्सपोर्ट करने वाले देशों की तुलना में ग्लोबल मार्केट में भारत के सामान और सर्विस अभी भी ठीक से नहीं दिखाए जाते हैं। ज़्यादा मार्केटिंग और ब्रांडिंग कॉस्ट एक्सपोर्टर्स को—खासकर एमएसएमई को—नए मार्केट में तेज़ी से आगे बढ़ने से रोकती है। बढ़ी हुई टैक्स डिडक्शन एक्सपोर्टर्स को इंटरनेशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा देगी और साथ ही असरदार फिस्कल बोझ भी कम करेगी। इस कदम से ब्रांड की विज़िबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डाइवर्सिफिकेशन होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा और लंबे समय तक ट्रेड सस्टेनेबिलिटी बेहतर होगी।

5.नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स का विस्तार

प्रस्तावः फियो प्रस्ताव करता है कि नई घरेलू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए सेक्शन 115 बीएबी के तहत 15% रियायती कॉर्पोरेट टैक्स दर को 31 मार्च, 2024 की पिछली कट-ऑफ तारीख से कम से कम पांच साल और बढ़ाया जाए।

औचित्यः ऐसे समय में जब भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग निवेश और सप्लाई-चेन रीलोकेशन के लिए ज़ोरदार मुकाबला कर रहा है, इस रियायती टैक्स व्यवस्था के खत्म होने से मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के तौर पर भारत का आकर्षण कम हो जाता है। इस योजना को बढ़ाने से पॉलिसी में निश्चितता आएगी, निवेश पर टैक्स के बाद रिटर्न बेहतर होगा, और सरकार के मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट-आधारित विकास के उद्देश्यों को मज़बूती मिलेगी। यह उपाय एक सुसंगत और प्रतिस्पर्धी वित्तीय ढांचा बनाकर, नए पूंजी निवेश, रोज़गार सृजन और भारत में उच्च मूल्य-वर्धित मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करके पीएलआई योजनाओं का भी पूरक होगा।

पश्चिम रेलवे विभिन्न गंतव्यों के लिए चलाएगी तीन जोड़ी स्पेशल ट्रेनें

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विशेष किराये पर 03 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार हैः

1) ट्रेन संख्या 09035/09036 बांद्रा टर्मिनस–उधना द्वि-साप्ताहिक स्पेशल [20 फेरे]

ट्रेन संख्या 09035 बांद्रा टर्मिनस–उधना स्पेशल प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को बांद्रा टर्मिनस से 09:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 15:05 बजे उधना पहुँचेगी। यह ट्रेन 30 जनवरी से 28 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09036 उधना–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार एवं शुक्रवार को उधना से 15:45 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 21:35 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी से 27 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में अंधेरी, बोरीवली, वसई रोड, विरार, वैतरणा, सफाले, केलवे रोड, पालघर, बोईसर,

वानगांव, दहाणू रोड, घोलवड, बोर्डी रोड, उमरगाम रोड, संजान, भीलाड, करमबेली, वापी, वलसाड, बिलीमोरा तथा नवसारी स्टेशनों पर रुकेगी।

इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 09035 भायंदर तथा ट्रेन संख्या 09036 अतुल, पारडी एवं उदवाडा स्टेशनों पर भी रुकेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

2) ट्रेन संख्या 09561/09562 बांद्रा टर्मिनस–ओखा साप्ताहिक स्पेशल [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 09561 बांद्रा टर्मिनस–ओखा स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 05:50 बजे प्रस्थान करेगी तथा उसी दिन 22:50 बजे ओखा पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09562 ओखा–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक मंगलवार को ओखा से 10:20 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 04:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2026 तक चलेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, सूरत, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, विरमगाम, सुरेन्द्रनगर, राजकोट, हापा, जामनगर, खंभालिया तथा द्वारका स्टेशनों पर रुकेगी। इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, एसी–3 टियर (इकोनॉमी), स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

3) ट्रेन संख्या 09005/09006 बांद्रा टर्मिनस–भिवानी सुपरफास्ट साप्ताहिक स्पेशल [10 फेरे]

ट्रेन संख्या 09005 बांद्रा टर्मिनस–भिवानी स्पेशल प्रत्येक बुधवार को बांद्रा टर्मिनस से 11:00 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 13:00 बजे भिवानी पहुँचेगी। यह ट्रेन 28 जनवरी से 25 फरवरी, 2026 तक चलेगी। इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09006 भिवानी–बांद्रा टर्मिनस स्पेशल प्रत्येक गुरुवार को भिवानी से 14:35 बजे प्रस्थान करेगी तथा अगले दिन 16:10 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुँचेगी। यह ट्रेन 29 जनवरी से 26 फरवरी, 2026 तक चलेगी। यह ट्रेन दोनों दिशाओं में बोरीवली, पालघर, वापी, सूरत, वडोदरा, रतलाम, मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बिजयनगर, नसीराबाद, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, कोसली तथा चरखी दादरी स्टेशनों पर रुकेगी।

इस ट्रेन में एसी–2 टियर, एसी–3 टियर, स्लीपर क्लास एवं जनरल सेकेंड क्लास कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 09035, 09036, 09561, 09562 एवं 09005 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर खुली है। ट्रेनों के ठहराव, समय एवं संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

अहमदाबाद- मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालनीक कारणों से ट्रेन संख्या 12933 मुंबई सेंट्रल–वटवा एवं ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी तौर पर परिवर्तन किया जा रहा है। दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक इस ट्रेन का आगमन/प्रस्थान मुंबई सेंट्रल (MMCT) के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस (BDTS) किया जाएगा।जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–वटवा कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी।

ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे समाप्त होगी।

अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान का समय यथावत रहेगा।

ट्रेनों के ठहराव, समय तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

डिजिटल से दुकानों तक भुगतान क्रांति, रेजरपे को आरबीआई से ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस

नई दिल्ली। भारत के तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक इकोसिस्टम में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जुड़ गई है। देश की प्रमुख फिनटेक कंपनी रेजरपे की ऑफलाइन भुगतान इकाई रेजरपे पीओएस को भारतीय रिजर्व बैंक से 'ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के रूप में काम करने का आधिकारिक लाइसेंस मिल गया है। यह मंजूरी न केवल रेजरपे के लिए एक बड़ी नियामकीय सफलता है, बल्कि भारत में डिजिटल भुगतान व्यवस्था को और अधिक मजबूत, सुरक्षित और व्यापक बनाने की दिशा में भी एक अहम कदम मानी जा रही है। इस लाइसेंस के साथ रेजरपे अब उन चुनिंदा कंपनियों की श्रेणी में शामिल हो गई है, जिनके पास आरबीआई के तीन प्रमुख लाइसेंस—ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर और ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर—एक साथ मौजूद हैं। भारत में डिजिटल भुगतान की यात्रा पिछले कुछ वर्षों में असाधारण रही है। यूपीआई, कार्ड, वॉलेट और क्यूआर कोड जैसे माध्यमों ने ऑनलाइन लेनदेन को बेहद आसान बना दिया है, लेकिन देश की बड़ी आबादी और व्यापार का एक बड़ा हिस्सा अब भी ऑफलाइन या इन-स्टोर भुगतान पर निर्भर है। छोटे दुकानदार, रिटेल स्टोर, रेस्तरां, मेडिकल शॉप, पेट्रोल पंप और सेवा क्षेत्र के असंख्य कारोबार ऐसे हैं, जहां ग्राहक और व्यापारी आमने-सामने लेनदेन करते हैं। ऐसे में ऑफलाइन भुगतान को सुरक्षित, तेज़ और नियमों के अनुरूप बनाना बेहद जरूरी हो जाता है।

रणोत्सव में सखी क्राफ्ट बाजार : एक महीने में 5 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री

अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों ने ली मुलाकात, 330 स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं के लिए 100 स्टॉल्स की व्यवस्था

(जीएनएस)। गांधीनगर : राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में विभिन्न पहलें की जा रही हैं। इन प्रयासों के अंतर्गत इस वर्ष कच्छ के रणोत्सव में 4 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक सखी क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया गया है। इस बाजार में स्वयं-सहायता समूहों से जुड़ी बहनों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए विशाल डोम में 100 स्टॉल्स की व्यवस्था की गई है। रणोत्सव में आने वाले पर्यटकों में सखी क्राफ्ट बाजार आकर्षण का केन्द्र बना है और अब तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है। इस क्राफ्ट बाजार में 330 स्वयं-सहायता समूह की महिलाओं को अलग-अलग चरणों में स्टॉल दिए जा रहे हैं, जिसमें गुजरात सहित देशभर से अन्य राज्यों की महिलाएँ भी शामिल हुई

हैं। क्राफ्ट बाजार की मुलाकात पर्यटकों के लिए यादगार स्मृति बनी है। क्राफ्ट बाजार के साथ लाइव संगीत कार्यक्रमों का आयोजन तथा कैफेटेरिया भी बनाया गया है। हस्तकला तथा हथकरघा से लेकर मिट्टी के बर्तनों, ज्वैलरी तथा होम डेकोर सहित पैकेज फूड की भी यहाँ बिक्री हो रही है। इस क्राफ्ट बाजार में परंपरागत हस्तकला तथा आधुनिक डिजाइन का अनूठा संयोजन देखने को मिल रहा है। अब तक 4.5 लाख से अधिक लोगों ने इस सखी क्राफ्ट बाजार की मुलाकात ली है।

गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अधीनस्थ गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड द्वारा सखी मंडल की बहनों के लिए हर वर्ष मार्केटिंग के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय स्तर के 2 सरस मेलों तथा क्षेत्रीय स्तर के 10-12 सरस मेलों का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष इसमें वृद्धि कर शॉपिंग फेस्टिवल, बड़े मॉडल में सखी मार्केट, फ्ली मार्केट, स्वदेशी मेलों तथा पर्यटन के कार्यक्रमों में भी सखी मंडलों के लिए वस्तुओं की बिक्री एवं ब्रैंडिंग की व्यवस्था की गई है।

अहमदाबाद- मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी परिवर्तन

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा परिचालनीक कारणों ट्रेन संख्या 12933 मुंबई सेंट्रल–वटवा एवं ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद-मुंबई सेंट्रल कर्णावती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में अस्थायी तौर पर परिवर्तन किया जा रहा है। दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तकइस ट्रेन का आगमन/प्रस्थान मुंबई सेंट्रल (MMCT) के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस (BDTS) किया जाएगा।जिसका विवरण निम्नानुसार हैः ट्रेन संख्या 12933 बांद्रा टर्मिनस–वटवा कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस से 13:55 बजे प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 12934 अहमदाबाद–बांद्रा टर्मिनस कर्णावती एक्सप्रेस दिनांक 26.01.2026 से 07.03.2026 तक मुंबई सेंट्रल के स्थान पर बांद्रा टर्मिनस पर 12:30 बजे समाप्त होगी। अन्य सभी स्टेशनों पर आगमन-प्रस्थान का समय यथावत रहेगा। ट्रेनों के ठहराव, समय तथा संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

26 जनवरी से 07 मार्च तक अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस 20 कोच रेक के साथ संचालित होगी

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा एवं बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए ट्रेन संख्या 22961/22962 मुंबई सेंट्रल–अहमदाबाद–मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस में अस्थायी रूप से 4 अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया गया है। यह ट्रेन दिनांक 26 जनवरी 2026 से 07 मार्च 2026 तक वर्तमान 16 कोचों के स्थान पर 20 कोच (20 coach Rake) के साथ संचालित की जाएगी। इस वृद्धि के अंतर्गत मौजूदा C14 कोच की क्षमता 44 सीटों से बढ़ाकर 78 सीटें की जा रही है। इसके अतिरिक्त चार नए एसी चेयर कार कोच C15, C16, C17 (प्रत्येक 78 सीटें) तथा C18 (44 सीटें) ट्रेन संरचना में जोड़े जा रहे हैं। इस तरह इस ट्रेन में 278 यात्री अधिक यात्रा कर सकेंगे। पश्चिम रेलवे यात्रियों को अधिक सुविधा, आरामदायक एवं सुरक्षित यात्रा उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयासरत है।

पलासवाड़ा के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत,रेलवे द्वारा सुधारकार्य प्रगति पर

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर प्रतापनगर–एकतानगर खंड पर संरक्षा में वृद्धि एवं ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कार्य प्रगति पर हैं।इसी क्रम में डभोई के पलासवाड़ा के पास स्थित लेवल क्रॉसिंग यानि समपार फाटक संख्या 20 पर एक रोड ओवर ब्रिज (ROB)का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण कार्य के दौरान सड़क यातायात को सुचारु बनाए रखने हेतु रेलवे द्वारा एक डाइवर्जन रोड विकसित की गई है। जनप्रतिनिधियों एवं सामाजिक संघटनों द्वारा इस लेवल क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जाम की समस्या से निजाद के लिए डाइवर्जन रोड को और चौड़ा करने की मांग पर अमल करते हुए वडोदरा मंडल द्वारा तेज गति से कार्य शुरू कर दिए है।

LC-20 (पलासवाड़ा) लेवल क्रॉसिंग पर वडोदरा की ओर जाने वाले मार्ग के एग्जिट पर स्थित स्पीड ब्रेकर को हटा दिया गया है, जिससे वाहनों के रुकने का समय कम हुआ है। इसी प्रकार, डभोई की ओर से आने वाली पुरानी सड़क पर भी स्पीड ब्रेकर को हटाया गया है। इसके अतिरिक्त सड़क की खराब एवं ऊबड़-खाबड़ सतह को दुरुस्त करते हुए पुनः डामरीकरण किया गया है।

पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर पहले लिफ्टिंग बैरियर (बूम) की लंबाई मात्र 6.50 मीटर थी,जिसे अब वडोदरा मंडल के इंजीनियरिंग विभाग तथा गुजरात राज्य सरकार के सड़क एवं भवन (R&B) विभाग द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण के उपरांत बढ़ाकर 8.20 मीटर कर दिया गया है। इसके फलस्वरूप अब डभोई एवं वडोदरा दोनों दिशाओं से आने वाले वाहनों के लिए पृथक-पृथक लगभग 8.00 मीटर चौड़ा सड़क मार्ग उपलब्ध हो सकेगा, जिससे यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा।

गुजरात राज्य सरकार के R&B विभाग द्वारा अप्रोच रोड को और चौड़ा करने का कार्य भी प्रगति पर है। चौड़ीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात रेलवे द्वारा सड़क के किनारे 100 मीटर एवं 200 मीटर की दूरी पर लेवल क्रॉसिंग संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे,जिनका निर्माण कार्य पहले ही पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही,दृश्यता बढ़ाने के उद्देश्य से हाइट गेज पर भी पेंटिंग की गई है।

वडोदरा मंडल द्वारा उठाए गए इन समन्वित और सुधारात्मक कदमों से आने वाले दिनों में पलासवाड़ा लेवल क्रॉसिंग पर यातायात जाम की समस्या से आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलेगी।